हिन्दुस्तान 1936

आतंकवाद पर दृढ़ता

चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक से निकले आखिरी संदेश में पहलगाम हमले का जिक्र न होना बहुत विचारणीय है। यही वजह है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वास्तव में, यह एक और प्रमाण है कि आतंकवाद संबंधी भारतीय शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस बीच, अमरनाथ यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले गुरुवार को उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सोचने पर मजबूर करती है। अमरनाथ यात्रा पहले ही आतंकियों के निशाने पर रही है और इस बार भी आतंकियों की गिद्ध-दृष्टि यात्रा पर हो, तो आश्चर्य की बात नहीं। विगत तीन दशक से तनाव की स्थिति में ही अमरनाथ यात्रा हो रही है। सुरक्षा बल शांतिपूर्ण यात्रा के लिए प्रयासरत हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रा सफलतापूर्वक संपन हो।

भारत विश्व स्तर पर इस कोशिश में लगा रहता है कि आतंकवाद का दबाव कम हो, पर दुर्भाग्य से दुनिया में अनेक देश नफा-नुकसान देखकर ही इस पर अपना रुख तय करते हैं। वास्तव में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी यही हुआ है। त्रासद विडंबना है कि एससीओ में शामिल देशों ने पहलगाम हमले को तो छोड़ दिया, पर बलूचिस्तान को अपनी घोषणा में शामिल कर लिया। जाहिर है, संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर न करना ही देशहित में है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव या घोषणा को पूरी तरह से नजरंदाज कर देने में ही भलाई है। शंघाई सहयोग संगठन की घोषणा में अगर यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तान की गड़बड़ी में भारत शामिल है, तो फिर भारत को ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। किसी भी विश्व स्तरीय सम्मेलन में जाने में कोई हर्ज नहीं है, वहां अपनी बात भी पुरजोर ढंग से रखनी चाहिए, पर वहां पारित होने वाले प्रस्तावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। भारत जब अपनी इस नीति को कुछ दिनों तक दोहराएगा, तो इससे शत्रु मानसिकता वाले देशों को साफ संदेश जाएगा। जिस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, दो देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई, उस हमले को तवज्जो न देने की रणनीति दरअसल हकीकत के साथ मखौल है। आतंकियों का पोषण करने वाले देश का कथित सदाबहार मित्र चीन हकीकत नहीं देखना चाहता है। हकीकत न देखने की गलती पाकिस्तान ने भी की थी और हम देख रहे हैं कि अब वह गरीबी और कमजोरी का किस तरह शिकार हो रहा है। आतंकवाद का समर्थन करते हुए यह देश अन्य देशों की दया पर आश्रित होता जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जवाब देते हुए उचित ही दोहराया है कि इस्लामाबाद को अपने भीतर झांकना चाहिए और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर देना चाहिए।

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक और उसकी घोषणा एक और प्रमाण है कि आतंकवाद संबंधी भारतीय शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

भारतीय नजरिये से देखें, तो अमेरिका और चीन, दोनों ही भारत में आतंकवाद के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। भूलना नहीं चाहिए, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सैन्य जनरल का अपने भवन में भोज के साथ स्वागत किया है। ऐसे घटनाक्रमों से भारत के लिए संदेश साफ है कि वह आंतरिक स्तर पर आतंकियों को जरा भी फन फैलाने का मौका न दे। इसके साथ ही, राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय नेताओं को देशहित में ज्यादा एकजुटता का परिचय देना होगा। विश्व में भारत हित की बात करने वालों को बल प्रदान करना होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 27 जून, 1950

कोरिया में युद्ध

महायुद्ध को समाप्त हुए पांच वर्ष नहीं हुए कि कोरिया में फिर युद्ध की ज्वाला भड़क उठी है। कोरिया भी रूस और अमरीका के बीच शीतयुद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। जापान ने कोरिया पर आज से चालीस वर्ष पहले सन् 1910 में अधिकार जमाया था। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में प्रमुख मित्र राष्ट्रों के प्रधानों ने यह घोषणा की थी कि जापान की पराजय के बाद कोरिया स्वतंत्र कर दिया जायेगा। जापान ने जब आत्मसमर्पण किया, तो कोरिया दो भागों में विभक्त हुआ। 38 अक्षांश से उत्तर वाला भाग रूस के फौजी नियंत्रण में गया और दक्षिणी भाग अमरीका के नियंत्रण में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी कि चुनाव के बाद कोरिया की अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना हो जाये और कोरिया को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाये। इस क्रम को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक कमीशन भी नियुक्त किया। इस कमीशन को कोरिया में वांछित सफलता नहीं मिली। उत्तरी कोरिया ने कमीशन के साथ सहयोग नहीं किया। सारे कोरिया में एक साथ चुनाव न होकर दक्षिणी कोरिया में अलग से चुनाव हुए। इन चुनावों का निरीक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के कमीशन ने किया था। उनके फलस्वरूप दक्षिणी कोरिया में अलग सरकार की स्थापना हुई। उत्तरी कोरिया में भी अलग चुनाव हुए और वहां के लिए अलग सरकार की स्थापना हुई, जिसे रूस ने मान्यता प्रदान की। उत्तरी कोरिया की सरकार साम्यवादी है और दक्षिणी कोरिया की सरकार लोकतंत्री। उत्तरी की सरकार को रूस का समर्थन प्राप्त है और दक्षिणी की सरकार को अमरीका का। इन दोनों सरकारों के आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे। उनकी सीमाओं पर आये दिन घटनायें होती रहती थीं। अब इन छुटपुट घटनाओं में बड़े पैमाने पर युद्ध का रूप धारण कर लिया है। क्या यह युद्ध की ज्वाला कोरिया की सीमा को लांघकर अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी, यह प्रश्न सहज ही पैदा होता है।

रूस ने उत्तरी कोरिया से अपनी फौजों को दिसम्बर 1948 में हटा लिया था। अमरीका ने अपनी फौजों को कुछ समय बाद हटाया। इस समय कोरिया में न रूस की फौजें हैं और अमरीका की। अतः मौजूदा संघर्ष उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। विदेशी सेनायें उसमें लिप्त नहीं हुई हैं।

बढ़ते टकरावों के बावजूद बढ़ता भारत

रहीस सिंह | विदेशी मामलों के वरिष्ठ अध्येता

आज जब शंघाई सहयोग संगठन जैसा मंच अपने उद्देश्यों से भटकता दिख रहा है, तब भी भारत अपने संकल्पों के साथ दुनिया को साथ ले चलने के लिए प्रतिबद्ध है।

फिलहाल दुनिया कई प्रकार के टकरावों से गुजर रही है। एक तरफ ये टकराव विश्व-व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया में सुरक्षा संकट पैदा कर रहे हैं। क्या 21वीं सदी का मौलिक चरित्र यही है अथवा कुछ ताकतों के 'ग्रेट गेम' ने उसे इस कीचड़ में धकेल दिया है? यदि ऐसा न होता, तो शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की किंगदाओ रोब मिनिस्टर्स (रक्षा मंत्रियों) समिट में जारी 'संयुक्त संवाद' में पाकिस्तानी आतंकवाद की कठोर शब्दों में निंदा की गई होती? ऐसे में, दो प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए आतंकवाद एक 'रवायती शब्द' है या वे वास्तव में इसके प्रति गंभीर हैं? और दूसरा, एससीओ व ब्रिक्स जैसे संगठन क्या अपने मूल से भटक चुके हैं?

पहलगाम में हुए आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद शंघाई सहयोग संगठन की किंगदाओ समिट ऐसा पहला अवसर था, जब पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया जा सकता था। हालांकि, इसकी उम्मीदें कम ही थीं, क्योंकि बीजिंग उसकी पीठ थपथपाता रहता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस समिट में जारी संयुक्त घोषणा-पत्र में आतंकवाद को लेकर प्रयुक्त की गई भाषा बहुत कमजोर थी। इसमें पाकिस्तान में हुई आतंकी घटनाओं का तो जिक्र किया गया था, लेकिन हाल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

भारत का रुख सही है। आज की इस गैर-संभ्रांतता वाली प्रतियोगिता के दौर में भी वह *वसुधैव कुटुम्बकम* का संदेश देने में समर्थ है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को आगे रखकर इस क्षेत्र को 'विस्तारित परिवार' के रूप में स्वीकार करने वाला बड़ा दिल रखता है। मगर चीन या अमेरिका जैसे देश इस मनोदशा से दूर खड़े दिख रहे हैं। भारत 'ग्लोबल साउथ' के साथ प्रमुख पहलों के माध्यम से व्यापारिक सहमतियों से लेकर रणनीतिक साझेदारियों तक, सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) भी ऐसे उद्देश्यों को समेट पाएगी?

भारत 'सिक्योर' सिद्धांत के जरिये सुरक्षा (सिक्योरिटी), आर्थिक सहयोग (इकोनॉमिक कोऑपरेशन), संबद्धता या जुड़ाव (कनेक्टिविटी), एकता (यूनिटी), संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता एवं पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपना ध्यान लगा रहा है। ये वे विषय हैं, जो दुनिया को 'कॉमन फैमिली' की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन चीन का उद्देश्य अलग है।

गौर से देखें, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बड़प्पन दिखाया था, अन्यथा पाकिस्तान की हस्ती मिट सकती थी। उस समय पाकिस्तान काफी दबाव में था। अमेरिकी अखबार *वॉल स्ट्रीट जर्नल* ने लिखा था- भारत ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करके पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि अब वह ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है। इमरान खान जेल में हैं, उसके चुनाव विवादित रहे हैं, देश आर्थिक संकट में है...।

यह अमेरिका और चीन को भी मालूम था कि कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को भारत के समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ऐसा होने पर पाकिस्तान बिखर जाता व दक्षिण एशिया में भारत चुनौतीविहीन ताकत बन जाता। मगर भारत ने संघर्ष रोकने पर सहमति जताई। वह आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 'सस्टेनेबिलिटी विद पीस' के साथ वह आगे बढ़ रहा है, इसलिए न केवल ग्लोबल साउथ, बल्कि दुनिया के अन्य भागों में स्थित देश भी उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे हैं। वैसे, भारत की क्षमता को अब से करीब ढाई दशक पहले ही गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ नील, पाउलो लेमे, सैंड्रा लॉसन, वारेन पियर्सन आदि ने पहचान ली थी। तभी उन्होंने दशक भर पहले *ड्रीमिंग विद ब्रिक्स : द पाथ टु 2050* नाम से एक रिपोर्ट पेश की थी।

इन अर्थशास्त्रियों को मालूम था कि दुनिया में महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं और आगे भी कम या ज्यादा गति से ये बदलाव होते रहेंगे, जिनका प्रभाव स्थायित्व, सुरक्षा और विकास पर पड़ता रहेगा। ऐसे में, इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। यानी ब्रिक्स, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण घटक है, विश्व की आर्थिक वृद्धि के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। इसके कारण भी थे।

दरअसल, उस समय जिस तरह के हालात नजर आ रहे थे, अर्थात- वैश्विक आतंकवाद, एशियन टाइगर्स का लंगड़ाती स्थिति में पहुंच जाना और फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में झटकों का अनुमान, जिसके परिणाम 2008 में दिख चुके थे, उनके लिए जिम्मेदार वही सत्ता-केंद्र थे, जो कभी विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार रहे, तो कभी शीतयुद्ध के लिए, अर्थात वाशिंगटन, मॉस्को, लंदन और पेरिस। अब इनमें एक नया नाम बीजिंग का जुड़ रहा था, जिसे 'दुनिया की इंडस्ट्री' के रूप में देखा जाने लगा था। भारत भी 'वर्ल्ड्स ऑफिस' के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। इसलिए ब्रिक्स से उम्मीदें बहुत थीं, परंतु इन उम्मीदों के बीच यह बात न जाने क्यों दरकिनार की जाती रही कि चीन भारत का सहयोगी नहीं हो सकता।

भारत जिस आतंकवाद से प्रभावित रहा है, उसका केंद्र पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का सदाबहार मित्र चीन है। फिर चीन पाकिस्तान की गर्दन पर पांव रखकर आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि भारत चीन के साथ भी वैश्विक प्रगति के लिए कदम बढ़ाना चाह रहा है। इसी का प्रमाण है कि ब्रिक्स जैसी संस्थाएं, अर्थात ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि के जरिये भारत ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था व रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

फिलहाल रियो डि जेनेरियो ब्रिक्स शिखर समिट में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन अनुपस्थित रहने वाले हैं। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील सहित अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर इस मंच पर भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। विशेषकर तब, जब ब्राजील भी भारत की तरह बीआरआई पहल से दूरी बनाए रखकर चीन को 'डिप्लोमेटिक कोल्डनेस' का संदेश दे रहा हो। ऐसे में, हम क्या यह कह सकते हैं कि आज 'ड्रीमिंग विद ब्रिक्स : द पाथ टु 2050' एक राह तलाश रही है और शंघाई सहयोग संगठन जैसा मंच जब अपने मूल उद्देश्यों से भटकता दिख रहा है, तब भी भारत अपने संकल्पों के साथ दुनिया को साथ ले चलने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शहरों को जाम से निकालने और संवारने की जरूरत

संजय चड्ढा | पूर्व अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार

बढ़ती शहरी आबादी को बसाने के लिए शहरों का जितना विस्तार हो रहा है, उसी अनुपात में बुनियादी ढांचा खड़ा करने की मशक्कत भी करनी पड़ रही है। इस जन-दबाव से निपटने के लिए आम तौर पर अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण, उनका चौड़ीकरण और फ्लाईओवर बनाने की नीति अपनाई जाती है। हालांकि, यह नीति उतनी कारगर नहीं साबित हो रही। लिहाजा राज्यों में अब मौजूदा बुनियादी ढांचे को ही बेहतर बनाकर अधिक टिकाऊ विकल्प की तलाश शुरू हो गई है। यदि इस दिशा में सही से काम हुआ, तो आशाजनक प्रगति हो सकती है।

इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र ने वाहनों को अधिक उपयोगी बनाने के इरादे से कार व बाइक पूलिंग नीति को मंजूरी दी, ताकि सड़क पर वाहनों की संख्या में कमी आए। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी वाहनों की भीड़भाड़ को प्रबंधित करने के लिए कुछ खास पॉइंट तय किए गए हैं, जहां से प्राधिकरण की टैक्सियां लोगों को इंडिया गेट तक लाती और पहुंचाती हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने 'वनसिटी, वन कम्यूट' नीति के तहत एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की घोषणा की है। इसमें एक ही टिकट पर सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।

विश्व बैंक का यह अनुमान है कि जाम के कारण भारतीय शहरों को सालाना 22 अरब डॉलर का नुकसान होता है।

दरअसल, हरेक जगह यह देखा जा रहा है कि लोग-बाग अपनी कार लेकर अकेले निकल पड़ते हैं। दिल्ली में ऐसी निजी कारें सड़कों का 75 प्रतिशत हिस्सा घेर लेती हैं। हालांकि यात्रियों की कुल भीड़ में इनकी हिस्सेदारी रोजाना 20 प्रतिशत से भी कम ही होती है। देश में 10 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास कार होने के बावजूद उन्हें सार्वजनिक रियायतों में व शहरी जमीन पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिलती है। मुंबई में नगरपालिका ऑडिट में पाया गया कि प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 30 प्रतिशत फुटपाथ कारों या उनके रखरखाव, मरम्मत आदि के कारण अवरुद्ध रहते हैं। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार से सड़कों पर दबाव कुछ कम हुआ है, मगर अपेक्षित गंतव्य तक इसकी अनुपलब्धता और टुकड़े-टुकड़े में योजना-निर्माण के कारण इसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।

उबर, ओला, रैपिडो व क्विक राइड जैसी सेवाओं ने लोगों की यात्रा के तरीके को बदल दिया है। इनके कारण बेकार पड़े वाहन भी उपयोग में आ गए हैं। मगर नीति बनाने में उदासीनता, बुनियादी ढांचे के सुधार में हीला-हवाली और इन सेवाओं के इस्तेमाल के लिए प्रेरक उपायों में कमी की वजह से इस दिशा में अपेक्षित विकास नहीं हो रहा। हालांकि, इन सेवाओं की मांग में कोई कमी नहीं है।

कोच्चि वाटर मेट्रो ने इस दिशा में नई राह दिखाई है। वहां एक ही टिकट-कार्ड से ई-ऑटो फीडर के साथ फेरी सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है। इसी तरह सूरत की क्षेत्रीय पार्किंग प्रणाली ने फुटपाथों के बेहतर उपयोग के लिए वहां पैदल यात्री प्लाजा बनाए हैं। ये कुछ ऐसे मॉडल हैं, जो दर्शाते हैं कि कैसे शहरी भूमि का अधिक कुशलता से उपयोग हो सकता है, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में प्रौद्योगिकी की अधिक से अधिक मदद ली जा सकती है।

शहरी नियोजन स्थानीय जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए। शहरों की सामूहिक परिवहन प्रणाली को मुख्यधारा में लाने के लिए स्पष्ट नियमों, प्रोत्साहनकारी उपायों व यात्रियों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की जरूरत है। निजी कारों की पार्किंग में ही शहरों का बड़ा स्थान चला जाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि जाम के कारण भारतीय शहरों को सालाना 22 अरब डॉलर का नुकसान होता है। इसमें प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर और उत्पादकता में कमी जैसे न दिखने वाले नुकसानों को देखें, तो सुधार और अधिक जरूरी हो जाता है।

शहरी जाम के संकट से निपटने के लिए हमें व्यस्त यातायात वाले इलाकों को सशुल्क बनाना होगा और इससे प्राप्त राशि को फुटपाथ बनाने या सार्वजनिक शटल सेवा शुरू करने में लगाना होगा। पायलट योजना के तहत स्कूलों व अस्पतालों के आसपास कम उत्सर्जन वाली गतिविधियों को प्रश्रय देने के साथ-साथ कम आबादी को बसाना चाहिए। छोटे-छोटे सुधारों से शहरों के परिदृश्य को बदला जा सकता है। भारतीय शहरों का भविष्य वाहनों के नहीं, लोगों के सुगम आवागमन में निहित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सबसे अनिवार्य अहिंसा

योग के पहले अंग का पहला स्वरूप अहिंसा है। अहिंसा की प्राप्ति होगी, तभी आदमी चित्त को एकाग्र कर पाएगा। अहिंसा का व्यापक अर्थ है- किसी को किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना। न वाणी से, न शरीर से। जब हम किसी की समाप्ति या उसे नुकसान पहुंचाने का संकल्प करते हैं, तो यह भी हिंसा है, यह नहीं होना चाहिए।

मां हिंस्यात सर्वाभूताणि। हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। इसलिए सनातन धर्म में लिखा है कि मच्छरों, कीट-पतंगों को भी मारने, वृक्ष-लताओं को काटने से भी पाप उत्पन्न होता है। यज्ञ में लकड़ी की जरूरत होती है, पेड़ काटे जाते हैं, तो जैसे यज्ञ से पुण्य मिलता है, ठीक उसी प्रकार हरा-भरा पेड़ काटने से पाप भी मिलता है। इसलिए लोग मनुष्यों की ही नहीं, किसी भी तरह से हिंसा नहीं करें। कौन-सा संप्रदाय होगा, कौन-सी ऐसी जाति होगी, जिसको हिंसा पसंद है? योग के पहले अंग यम का पहला स्वरूप अहिंसा है। जिसे वेदों ने सबसे पहली बार समाज में प्रकट किया था- किसी भी प्राणी के साथ हिंसा मत करो। ऐसे आख्यान भी आए हैं, जब तितली के पंख में कांटे को छुआ दिया, तो दंडस्वरूप सूली पर बैठना पड़ा। शास्त्रों में वर्णित हैं ऐसे प्रसंग। कितना बड़ा चिंतन है महर्षि पतंजलि का- *अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः*, अर्थात जब योगी का अहिंसा भाव स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर त्याग देते हैं।

यम का दूसरा अंग है सत्य। वेदों ने कहा- *सत्यम वद।* यह किसी एक जाति या काल के लोगों के लिए नहीं कहा था, सबके लिए कहा था। सत्य सभी को बोलना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा- *सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम*, अर्थात सत्य में यदि कोई प्रतिष्ठित है, तो उसकी वाणी में संपूर्ण क्रियाओं के फल आ जाएंगे। सत्य बोलने वाला यदि कह देगा, तो पापी भी स्वर्ग चला जाएगा। सत्य की आवश्यकता पूरे संसार को है। सत्य बोलने से सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है।

यम का तीसरा अंग है अस्तेय, अर्थात, चोरी का अभाव होने पर योगी के सामने हर प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते है। पूरी दुनिया की समस्या है कि लोग छल-कपट, अनेक तरह के गलत हथकंडों से दूसरे की वस्तु, जमीन, संसाधनों को अपना बना लेते हैं, संपूर्ण मानव जाति ही चोरी से त्रस्त है।

कितना बड़ा चिंतन है महर्षि पतंजलि का- अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अर्थात जब योगी का अहिंसा भाव स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर त्याग देते हैं।

योग के लिए अपरिग्रह जरूरी है। उपनिषदों में लिखा गया है कि संग्रह उतना ही करना चाहिए, जितने में जीवन का निर्वाह हो जाए। मगर आज जो लोग योग के प्रचार में लगे हैं, उनमें से ज्यादातर बड़े परिग्रही हैं। जबकि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है- अपरिग्रही को सभी तरह के फल की प्राप्ति होगी, उसे बैठे-बैठे ही सभी रत्नों की प्राप्ति होगी।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

जगदीप धनखड़ | उप-राष्ट्रपति, भारत

तक्षशिला विश्वविद्यालय इसलिए तक्षशिला बना, क्योंकि पाणिनी और चाणक्य यहां थे। नालंदा इसलिए प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि शीलभद्र इसके प्रमुख थे।... इसलिए दोस्तो, भारत के विविधता भरे शैक्षिक परिदृश्य को दूरदर्शी लोगों की दरकार है।

अनुलोम-विलोम

एमएसएमई दिवस

बड़े कारगर साबित हो रहे छोटे-छोटे उद्योग

आज, यानी 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का मकसद है, दुनिया भर के देशों द्वारा अपने-अपने यहां एमएसएमई की बेहतरी पर ध्यान देना। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि आकलन है कि बढ़ते वैश्विक कार्यबल को संभालने के लिए साल 2030 तक 60 करोड़ नौकरियों की जरूरत होगी, जिनकी पूर्ति में एमएसएमई काफी कारगर साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र तमाम सरकारों से अपेक्षा करता है कि वे अपने यहां इन उद्यमों के विकास को पर्याप्त तवज्जो दें।

भारत में भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह क्षेत्र न सिर्फ देश की जीडीपी में करीब 30 फीसदी का योगदान देता है, बल्कि कुल निर्यात में भी 45 फीसदी की अहम भागीदारी निभाता है। यह देश में लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में तो ऐसे उद्योग कई घरों की आजीविका का एकमात्र साधन हैं। यही कारण है कि सरकारें भी एमएसएमई उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उनका विस्तार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देती हैं। कहा भी जाता है कि ऐसे उद्योग ही देश के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की नई राह तैयार करेंगे, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आएगी। इतना ही नहीं, नवाचार को बढ़ाने में भी ऐसे उद्योग काफी काम आते हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देकर और नियमन-प्रक्रिया को सरल व लचीला बनाकर भी सरकारें ऐसे उद्योगों को राहत प्रदान करने का काम करती हैं।

हालांकि, यह भी सच है कि अपने यहां एमएसएमई क्षेत्र को कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। खासतौर से वित्त-पोषण एक बड़ी समस्या है। मगर इस समस्या का भी समाधान निकाला जा रहा है। इसी वर्ष फरवरी में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर रही थीं, तब उन्होंने एमएसएमई को देश के विकास का महत्वपूर्ण इंजन माना था और ऐसे कई प्रस्तावों का एलान किया, जिनसे इस क्षेत्र को अपने विस्तार का मौका मिलेगा। यहां तक कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कर्ज की सीमा भी पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी और सूक्ष्म उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की।

जाहिर है, भारत एमएसएमई क्षेत्र पर खासा ध्यान दे रहा है। संभवतः यह भी कारण है कि अपने देश में अब इन उद्यमों की संख्या बढ़कर 5.7 करोड़ हो गई है। कहने का मतलब यही है कि ये छोटे-छोटे उद्योग बड़े काम के साबित हो रहे हैं।

दीप्तांशु, टिप्पणीकार

सिर्फ बड़ी कंपनियों का ख्याल रखा जा रहा

इससे इनकार नहीं है कि केंद्र व राज्य सरकारें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के हित में कदम उठा रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जितना ख्याल बड़ी कंपनियों का रखा जाता है, उतना छोटे उद्योगों का नहीं रखा जाता। यकीन न हो, तो बीते कुछ वर्षों पर गहराई से नजर डाल देखिए। आपको कई सच्चाइयों का खुद-ब-खुद एहसास हो जाएगा।

दरअसल, भारत के साथ समस्या यह रही कि यहां 'मेक इन इंडिया' अभियान बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सका। 'आत्मनिर्भर भारत' की भी कमोबेश यही गति रही। ऊपर से नोटबंदी जैसी नीतियां अपनाई गईं, जिन्होंने छोटे उद्यमियों की कमर तोड़ दी, क्योंकि ये छोटे-छोटे उद्योग आमतौर पर नकदी लेन-देन में ही अपना कारोबार करते हैं। स्थिति यह रही कि नोटबंदी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की हजारों कंपनियों को अपना कारोबार समेटना पड़ा। इसके बाद जो थोड़ी-बहुत सांस बची थी, उसे जीएसटी द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया। ऐसे-ऐसे कानून बना दिए गए हैं, जिनके पालन में इन उद्योगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उद्यमी इन कानूनों में ही उलझकर रह जाते हैं। उनके लिए जीएसटी रिटर्न भरना किसी चुनौती से कम नहीं है। निस्संदेह, इस दावे में सच्चाई हो सकती है कि इन कदमों से भारत में दो लाख फर्जी कंपनियों को बंद किया गया है। मगर सच यह भी है कि इन कंपनियों में वे छोटे-छोटे उद्योग भी शामिल हैं, जिनमें दो-चार या पांच लोग काम करते थे और जैसे-तैसे गुजारा करते थे। इन कंपनियों के बंद होने का एक नुकसान यह भी हुआ कि अब छोटी-छोटी चीजें अपने देश में कम बनने लगी हैं, ज्यादातार चीन से आयात की जाती हैं।

आज देश के एमएसएमई के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। सबसे बड़ी समस्या वित्त से जुड़ी है। उनको बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती। कर्ज की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में उद्यमियों को उलझाने की मानसिकता खत्म नहीं हुई। इसी तरह, बुनियादी ढांचे पर भी काफी काम किए जाने की जरूरत है। आज भी ये उद्यम बिजली, परिवहन, संचार जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझते देखे जा सकते हैं। फिर, बाजार तक भी इनकी पहुंच उस तरह नहीं है, जैसी होनी चाहिए। सरकारें प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन प्रोत्साहन के बजाय प्रतिस्पर्द्धा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर, अभी इन उद्योगों की बेहतरी के लिए काफी काम किए जाने की जरूरत है। इन पर हमें ध्यान देना ही होगा, अन्यथा देश का समग्र विकास प्रभावित हो सकता है।

हतेश मिश्र, टिप्पणीकार

चिंतन

एससीओ मंच से आतंकवाद पर चीन-पाक को कड़ा संदेश

आतंकवाद पर कड़ा संदेश देना जरूरी है। चीन का दोगलापन नहीं चलेगा। एक तरफ चीन वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, दूसरी तरफ चीनी प्रभुत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संयुक्त बयान में पाकिस्तान को खुश करने के लिए पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का जिक्र तक नहीं किया जाता है, बल्कि बलूचिस्तान में चल रहे बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोह में इशारे में भारत के हाथ का उल्लेख किया जाता है। चूंकि एससीओ सम्मेलन चीन में हो रहा है, ऐसे में संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों के हितों को तवज्जो दिलाना चीन का ही दायित्व है। पहलगाम की ताजा आतंकी घटना का एससीओ के बयान में शामिल नहीं करना चीन के आतंकवाद के प्रति दोहरे रवैये को इंगित करता है। भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर चीन और पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है कि आतंकवाद को लेकर सिलेक्टिव रुख नहीं चलेगा। इसका नतीजा हुआ कि एससीओ का संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। भारत ने साफ कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। शांति और समृद्धि आतंक के साथ नहीं रह सकते। एससीओ सदस्यों से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की जरूरत है। यूं तो एससीओ बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन आतंकवाद को लेकर भारत के कड़े रुख व पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट के हाथ की बात जगजाहिर होने के बावजूद एससीओ के संयुक्त बयान में आतंकी घटना की निंदा न होना व पाकिस्तान को लेकर कुछ भी नहीं कहा जाना, एससीओ के लक्ष्य की सार्थकता को ही निरर्थक बना रहा है। एससीओ के ध्येय में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात है। चीन के चलते कभी भी एससीओ में भारत के हितों की रक्षा नहीं होगी, इसलिए भारत का इसमें बना रहना व्यर्थ है, समय व ऊर्जा गंवाने जैसा है। चीन कभी दिल से भारत का हित चाहेगा भी नहीं, इसलिए उसकी छतरी वाले इस संगठन में भारत के रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। 2001 में स्थापित, एससीओ में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं- बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चीन की गुप्त कोशिश एससीओ में बांग्लादेश को भी शामिल कराने की है, हालांकि अभी तक इस बाबत कुछ कहा नहीं गया है, पर एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की शिखर बैठक से कुछ दिन पहले 19 जून को चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चीनी शहर कुनमिंग, युन्नान में पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हुई। बांग्लादेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन और पाक-बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकी के बाद भारत के खिलाफ चीन, पाक व बांग्लादेश का त्रिकोण बन रहा है। वर्ष 2024 में दिसंबर में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद सैन्य और आर्थिक सहयोग शुरू हुआ है। भारत को जहां आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख बनाए रखना है, वहीं इस नए त्रिकोण से निपटने के लिए भी सामरिक व कूटनीतिक तैयारी करनी है।

युद्ध विराम
प्रमोद भार्गव

एटमी अस्त्रों के बहाने युद्ध के मायने

इजरायल ने ट्रंप की शह पर ईरान पर मिसाइलों से हमले इसलिए किए, जिससे उसकी परमाणु क्षमता को नष्ट कर अपने देश की रक्षा कर ली जाए। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए और दावा किया कि इन परमाणु संयंत्रों को इतना नुकसान हो गया है कि अब कई साल तक ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो गई है। वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने कहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान बम बनाने से बहुत दूर हो गया है। तब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला ?

ईरान-इजरायल के बीच 12 दिन युद्ध चला, बीच में अमेरिका द्वारा ईरान के एक साथ तीन परमाणु ठिकानों पर हमला और जवाबी कार्यवाही में ईरान का कतर में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर अल-उदैद हमले का आखिरी परिणाम क्या निकला? कहना मुश्किल है। यह युद्ध और इसमें नटखट बच्चे की तरह हरकतें देखने में आई हैं। ये हरकतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही हैं। इजरायल ने ट्रंप की शह पर ईरान पर मिसाइलों से हमले इसलिए किए, जिससे उसकी परमाणु क्षमता को नष्ट कर अपने देश की रक्षा कर ली जाए। इसी दौरान आ बैल मुझे मार कहावत को चरितार्थ करते हुए अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए और दावा किया कि इन परमाणु संयंत्रों को इतना नुकसान हो गया है कि अब कई साल तक ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा।

ये बम बनाना तब और मुश्किल हो गया है, जब इजरायल ने ईरान पर किए पहले ही हमले में वहां के अनेक परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था। युद्ध के ग्यारहवें दिन ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। परंतु इस घोषणा के बाद दोनों ही देशों ने एक-दूसरे पर हमले किए। यही नहीं, ईरान ने भी अमेरिका के अरब देशों में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के संदर्भ में ट्रंप ने कहा कि उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया और ट्रंप ने दावा कर दिया कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू हो गया है। कतर ने भी इस युद्ध विराम में मध्यस्थता की भूमिका अदा की, लेकिन इस युद्ध की जरूरत क्या थी, यह सवाल जस का तस बना हुआ है।

दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो गई है। वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने कहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान बम बनाने से बहुत दूर हो गया है। तब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला ? परमाणु हथियारों के जानकार कह रहे हैं कि ईरान के पास 20 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता थी, जो अब घटकर 6 बम बनाने की रह गई है। जबकि ट्रंप का घोषित लक्ष्य था कि ईरान यूरेनियम क्षमता बढ़ाने के लिए जिस तेजी से संवर्धन कर रहा है, वह तय सीमा से बाहर की बात होती जा रही है। लेकिन ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता कम भले ही हो गई हो, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह तथ्य तीनों देशों के आए बयानों से सत्यापित होता है। अतएव ईरान पर किया गया बेवजह हमला, कुछ वैसा ही रहा जैसा 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने ईराक पर यह कहते हुए किया था कि ईराक के पास बड़ी मात्रा में जैविक हथियार हैं। जबकि युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद अमेरिका जैविक हथियार होने का कोई प्रमाण दुनिया को नहीं दे पाया। हां, सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतारने के बाद तेल के कुओं पर जरूर कब्जा कर लिया। बावजूद यह आशंका बनी हुई है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो बम गिराए हैं, उनसे यदि रिसाव होता है तो एक बड़े भू-क्षेत्र में परमाणु विकिरण का संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु संवर्धन प्रतिष्ठान फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अत्याधुनिक बी-2 घातक बमों से हमला किया था। इन बमों को सटीक निशाने पर दागने

के लिए अमेरिकी पनडुब्बियों ने पहले दो मिसाइलों से बम गिराए, जिससे बंकर बस्टर बमों के लिए मैदान साफ किया गया। इसके बाद आसमान से एक के बाद एक 14 जीबीयू-57 बी बंकर बस्टर दाग दिया। इस पूरे अभियान को नतीजे तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने 15 युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया। उपग्रह द्वारा निर्देशित 2400 किलो परमाणु विस्फोटक साथ ले जाने वाला यह बम जमीन में घूमता हुआ 60 मीटर गहराई तक जाने के बाद विस्फोट करके अपने लक्ष्य साधने में सफल हुआ। अमेरिका ने तीनों ठिकानों पर 14000 किलो विस्फोटक वाले बम गिराए थे, अतएव भविष्य में विकिरण का खतरा पैदा हो सकता है? अमेरिका ने जिन तीन परमाणु स्थलों पर हमला किया है, वह सभी ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन ठिकाने हैं।

अमेरिका का यह हमला दुनिया के अंतरराष्ट्रीय कानून और अपने ही देश के कानूनों की परवाह नहीं करता है। इसीलिए अमेरिका के भीतर इस परमाणु हमले को लेकर अमेरिकी जनमत विभाजित दिखाई दे रहा है। दरअसल, किसी देश पर हमला करने के लिए ट्रंप को अमेरिकी संसद में हमले का प्रस्ताव लाकर अनुमोदन की जरूरत थी, परंतु उन्होंने इस प्रक्रिया पर अमल नहीं किया। जबकि अमेरिका की ही बात करें तो अप्रैल 2003 में इराक पर हमले के समय बुश ने संसद से मंजूरी ली थी। इसलिए ट्रंप के समर्थकों के साथ विपक्ष भी नाराज है। नाटो देश भी इस युद्ध पर सहमत दिखाई नहीं दिए। रूस और चीन खुले रूप में ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। चूंकि भारत के ईरान और इजरायल दोनों से ही मधुर, कूटनीतिक संबंध हैं, इसलिए तटस्थ रहते हुए शांति की पहल करता रहा। अंतरराष्ट्रीय कानून परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरुद्ध अमानुषिक कृत्य मानते हैं। इनके उपयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के कठोर आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वे सब अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों के दबाव में रहती हैं। यही देश इन संस्थानों को चलाने के लिए धन मुहैया कराते हैं और इन्हीं देशों के लोग इन संस्थानों के सदस्य होते हैं, इसलिए यहां पक्षपात साफ दिखाई देता है। अब ईरान में परमाणु विकिरण फैल भी जाए, तब भी अमेरिका के विरुद्ध कोई प्रतिबंध लगाना असंभव है।

ईरान ने अमेरिकी सहयोग से 1957 में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान को सहयोग करना बंद कर दिया। बावजूद पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु बम बना लेने का आरोप लगाते रहे। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने के बाद भी ईरान पर शंकाएं की जाती रहीं। इजरायल ने जासूसी करके कुछ ऐसे सबूत जुटाए जिनसे यूरेनियम संवर्धन की आशंका मजबूत हुई। ईरान ने पहले संवर्धन रोक दिया था, लेकिन इजरायल की बढ़ती सामरिक क्षमता के चलते उसने गुपचुप परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इस कारण ईरान पर पश्चिमी देशों ने यह कहते हुए अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे कि ईरान परमाणु बम बनाने के निकट पहुंच गया है। बाद में कई साल चली वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रतिबंध हटा लिए थे। इस समझौते में ईरान को असैन्य यूरेनियम संवर्धन को 3.67 प्रतिशत तक रखना मान्य कर लिया था। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने समझौते से हाथ खींच लिए और ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। मई 2025 में आईएईए ने दावा किया कि ईरान के पास 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 408 किलो है। इससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसे ही नष्ट करने के लिए युद्ध और युद्ध विराम का यह खेल खेला गया, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। तब फिर इस युद्ध के परिणाम क्या निकले।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं। लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।)

शुभ उड़ान
प्रो. आर.के. जैन

अंतरिक्ष से भारत की हुंकार

जब एक भारतीय ने सितारों को छू लिया, तो वह पल केवल अंतरिक्ष की यात्रा नहीं था, वह 140 करोड़ दिलों की धड़कनों का उत्सव था, भारत की आत्मा का उद्घोष था, हमारी सांस्कृतिक विरासत का ब्रह्मांड में लहराता तिरंगा था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने जब ड्रैगन कैप्सूल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की ओर कदम बढ़ाया, तो वह केवल एक अंतरिक्ष यात्री की उड़ान नहीं थी, वह भारत के सपनों, संकल्प और वैज्ञानिक शक्ति की अनंत यात्रा थी। यह वह क्षण था जब भारत ने न केवल धरती की सीमाएं लांघीं, बल्कि सितारों के पार अपनी पहचान को अमर कर दिया। 25 जून 2025 को, भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 बजे, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फाल्कन-9 रॉकेट आकाश को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार थे भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला, जो एक्सिओम-4 मिशन के पायलट की भूमिका में थे। उनके साथ थे कमांडर पैगी व्हिटसन (पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री, अमेरिका), मिशन विशेषज्ञ स्लावोश उज्नांस्की-विस्निव्स्की (पोलैंड), और तिबोर कपु (हंगरी)। यह मिशन नासा, एक्सिओम स्पेस और स्पेसएक्स की साझेदारी का प्रतीक है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का समर्थन प्राप्त है। लॉन्च के महज 10 मिनट बाद, शुभांशु और उनकी टीम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। यह 14-दिवसीय मिशन 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों का मंच है, जिनमें सात इसरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। ये प्रयोग भारत की वैज्ञानिक प्रगति को विश्व मंच पर चमकाने का अवसर हैं, जो न केवल तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि भारत के भविष्य के अंतरिक्ष सपनों का आधार भी है। शुभांशु की यह यात्रा 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक सोवियत सैल्यूट-7 मिशन के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में शानदार वापसी है। 41 साल बाद, शुभांशु आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम स्याही से लिखा जाएगा। यह केवल एक व्यक्ति की उड़ान नहीं, बल्कि भारत की उस जिजीविषा का प्रतीक है, जो सीमाओं को तोड़कर अनंत की ओर बढ़ रही है। इस मिशन की आत्मा भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। शुभांशु ने अपने साथ एक सॉफ्ट टॉय हंस लिया, जिसे भारतीय शास्त्रों में ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है। यह हंस अंतरिक्ष की अनंतता में तैर रहा है, जैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत सितारों के बीच अपनी चमक बिखेर रही हो। लॉन्च के दौरान, उनके कंधे पर लहराता तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं था, वह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, गर्व और एकता का प्रतीक था। यह तिरंगा गर्व से कह रहा था कि यह उड़ान केवल शुभांशु की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है, जो खेतों से लेकर प्रयोगशालाओं तक, सपनों को हकीकत में बदल रहा है। शुभांशु ने भारतीय खान-पान को भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आम का रस, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा उनके साथ गए, जो वे अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा, वे माइक्रोग्रैविटी में योग करने की योजना बना रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच पर एक अनूठा प्रदर्शन होगा। यह वह क्षण है जब परंपरा और प्रौद्योगिकी ने एक-दूसरे का हाथ थामा, और भारत ने साबित कर दिया कि वह न केवल विज्ञान में, बल्कि संस्कृति में भी अग्रणी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है। शुभांशु सात भारतीय प्रयोग करेंगे, जिनमें माइक्रोग्रैविटी में मूंग और मेथी के अंकुरण का अध्ययन और मांसपेशियों की हानि का विश्लेषण शामिल है। ये प्रयोग भारत और अमेरिका की साझेदारी का परिणाम हैं और इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेंगे। गगनयान, जो 2026 में लॉन्च होने वाला है, भारत का पहला स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। शुभांशु, जो इसके लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, इस मिशन के लिए अमूल्य अनुभव ला रहे हैं। कुल 60 से अधिक प्रयोग, जिनमें सामग्री विज्ञान, जैविक अनुसंधान और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रैविटी के प्रभाव शामिल हैं, भारत के भविष्य के मिशनों—जैसे 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए नींव रखेंगे। यह वह दस्तक है जो ब्रह्मांड के दरवाजे पर भारत की उपस्थिति को अमर कर रही है, न केवल एक यात्री के रूप में, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में। यह न कोई अंत है, न कोई पड़ाव। यह तो एक नई शुरुआत है, उस भारत की, जो अब ब्रह्मांड की गहराइयों में अपनी कहानी लिख रहा है, और जिसकी गूंज सितारों से सितारों तक अनंत काल तक गूंजेगी। यह भारत का वह उद्घोष है, जो कहता है कि "हम आए हैं, और हम रहेंगे, धरती पर, आकाश में, और सितारों के पार!"

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

चेतना की चौथी अवस्था है शिव तत्व

संकलित
दर्शन

शिव को अनुभव करने का प्रयास न करें। आपको बस उस पल में मौजूद रहना है और निश्चिंत रहना है, शिव तत्व पहले से ही वहां मौजूद है। हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं - जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चेतना की एक चौथी अवस्था भी है, जहां हम न तो जाग्रत होते हैं, न स्वप्न देखते हैं और न ही सोते हैं। इसका अनुभव ध्यान में होता है। उस चौथी अवस्था की झलक को ही शिव तत्व कहा जाता है। उपनिषद कहते हैं शिवम्, शांतम्, अद्वैतम्, चतुर्थम्, मन्यन्ते, सा आत्मा, सा विज्ञेय। अर्थात शुभ, शांतिपूर्ण चौथी अवस्था, जहां दो नहीं हैं, वह तुम्हारा स्वरूप है, वही जानने योग्य है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप केवल एक नाम नहीं हैं, मात्र एक रूप नहीं हैं। आप वह प्रकाशमान चेतना हैं जो शिव तत्व है। शिव का मंदिर पत्थरों से नहीं मनुष्य की चेतना से बना है। वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है, वह सत्ता जिसमें हर जीवन समाया है, वह रहस्यमय शिव तत्व है। नटराज स्वयं चेतना हैं, उनमें पांच तत्वों को दर्शाया गया है। चेतना का नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह ब्रह्मांड संघर्ष या कष्ट नहीं दे रहा है; यह हर क्षण उत्सव मना रहा है। ये आनंद है, जो यह नहीं जानता, वह दुःखी होता है, निराश होता है, पीड़ित होता है। जो यह जानता है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक नृत्य है, उसे आनंद मिलता है। यह सत्य शिव तत्व है।

जमींदार और मजदूर के कर्म का फल

संकलित
प्रेरणा

एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की साथ ही मौत हुई। दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने जमींदार से कहाः आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर से कहाः अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से यहां रहोगे। जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहाः भगवन, आप ने मुझे यह सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूं। प्रतिदिन मंदिर जाता था। देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीजें दान करता था। धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता ही रहता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछाः तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर ने कहाः भगवन, मैं गरीब मजदूर था। दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहां से जितना मिलता था, उसी में परिवार के साथ गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल होता तब मंदिर में आरती करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने-जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले। धर्मराज ने जमींदार से कहाः आपने सुन ली न मजदूर की बात? भगवान धन-दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को मिले त्वरित न्याय

देश मे बढ़ रहे महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को त्वरित न्याय के लिए फास्टट्रैक कोर्ट के गठन पर गृहमंत्री अमित शाह ने जोर दिया। वाराणसी मे आयोजित एक बैठक मे गृहमंत्री ने चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस विषय पर बात की ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। देश मे जिस तेजी से यौन अपराध बढ़ रहे हैं उसकी रोक थाम के लिए कदम उठाना जरूरी है। देश मे जिस तेजी से दुष्कर्म की घटनाएं आए दिनों घट रही है उसकी रोक थाम के लिए फास्टट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए ताकि प्रभावितों को न्याय मिलने मे देरी ना हो और अपराधी बच कर न निकल पाए।

-कांतिलाल मांडोत, सूरत

करंट अफेयर

वियतनाम ने आठ अपराधों के लिए मृत्युदंड किया खत्म

वियतनाम ने कानूनी सुधारों के तहत आठ अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया। इस फैसले से देश के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में कारावास की सजा काट रहे रियल एस्टेट कारोबारी को राहत मिल सकती है। वियतनाम में कानूनी सुधारों के तहत आठ अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया, जिसमें सरकार को हटाने की कोशिश करना, राज्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना, नकली दवा बनाना व बेचना, युद्ध शुरू करना, जासूसी करना, मादक पदार्थों की तस्करी, गबन और रिश्वत लेना शामिल है। सरकारी मीडिया के अनुसार, वियतनामी सांसदों ने बुधवार को सुधारों को पारित किया।

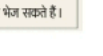

कानूनी सुधारों के बाद वियतनाम के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में संलिप्तता के लिए मृत्युदंड की सजा पाने वाली ट्रुओंग माई लान को राहत मिल सकती है। लान के वकील फान मिन्ह होआंग ने बृहस्पतिवार को 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि रियल एस्टेट कंपनी 'वान थिन्ह फाट' की 67 वर्षीय अध्यक्ष अब नए नियमों के अनुसार 'मृत्युदंड से छूट के लिए पात्र' होंगी। लान को 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए फांसी की सजा दी गयी है।

ऑफ बीट

फायदा या नुकसान स्क्रीन कंटेंट पर निर्भर करता है

आज लोग अपना ज्यादातर वक्त स्मार्टफोन, कम्प्यूटर, टैबलेट, टेलीविजन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे डिजीटल स्क्रीन पर बिताते हैं और इस पर दुनियाभर में विशेषज्ञों तथा माता-पिता के बीच बहस छिड़ी हुई है कि क्या छोटे बच्चों को इन डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल करने देना चाहिए। तो फिर 'स्क्रीन टाइम' का बच्चे के तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक विकास पर वास्तविक प्रभाव क्या है? कई बाल चिकित्सा संघ बचपन में खासतौर से पांच साल की आयु तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित रखने की सलाह देते हैं लेकिन अनुसंधान से पता चलता है कि यह तस्वीर पूरी तरह से सच नहीं है। बच्चे स्क्रीन टाइम में क्या देखते हैं, वह इसके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कई अध्ययनों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्क्रीन के लंबे समय तक उपयोग से बच्चों में आंखों की थकान, आंखों में सूखापन और निकट दृष्टि दोष हो सकता है। इसके अलावा, बच्चों को जिस प्राकृतिक उत्तेजना की जरूरत होती है, तकनीक उसकी जगह नहीं ले सकती और न ही लेनी चाहिए।

X ट्रेंड

प्रति व्यक्ति आय बढ़ी

डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारने व अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद मिली है।
-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

नवाचार को बढ़ावा

हमारे युवा वाकई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, तकनीक से प्रेरित और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह आपसी विकास का एक अवसर है, जो व्यवसायों के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और साथ ही हमारे राज्य के भविष्य को भी सशक्त बनाएगा।
-एन चंद्रबाबू नायडू, सीएम, आंध्र प्रदेश

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती में अग्रणी है। हम शीघ्र ही प्राकृतिक खेती को अधिक प्रोत्साहन देने वाली योजना बनाएंगे, मंडियों में दोनों प्रकार की फसलों के उपार्जन और विक्रय की व्यवस्था करेंगे, ताकि किसान परेशान न हों।
-डा. मोहन यादव, सीएम, मप्र

दुश्मनों की जरूरत नहीं

जब जोहरान ममदानी अपना मुंह खोलते हैं, तो पाकिस्तान की पीआर टीम छुट्टी ले लेती है। भारत को उनके जैसे सहयोगी के रूप में दुश्मनों की जरूरत नहीं है। वह न्यूयॉर्क से सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं।
-अभिषेक सिंघवी, कांग्रेस सांसद

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

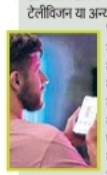

इजरायल-ईरान युद्धविराम

राहत की सांस

इजरायल और ईरान द्वारा युद्धविराम पर सहमति से दुनिया ने राहत की सांस ली है। बारह दिन के युद्ध के बाद इजरायल और ईरान ने दोनों देशों के बीच अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए समझौते के बाद जंग थम गई है। हालांकि, अभी अस्थिरता बनी हुई है, पर इसका विश्व युद्ध जैसी स्थिति में पहुंचना टल गया है। युद्धविराम एक राजनयिक उपलब्धि के साथ चेतावनी की घंटी भी है क्योंकि थोड़ी सी गलतफहमी भी क्षेत्र में फिर आग भड़का सकती है। अमेरिका द्वारा ईरान के नाभिकीय ठिकानों पर सीधे हमले और ईरान द्वारा कतर के अमेरिकन सैनिक अड्डों पर बम गिराने के बाद युद्ध का दायरा बहुत बढ़ गया था क्योंकि रूस और चीन ने अमेरिकन हमले की निन्दा करते हुए टकराव में अपनी संलिप्तता की ओर कदम बढ़ाए थे जिससे मध्यपूर्व में सभी महाशक्तियों का एक दूसरे से टकराव संभव हो गया था। मजेदार बात है कि तेहरान और तेलअबीब, दोनों ने विजय का दावा किया है। इजरायल ने जोर दिया है कि उसने अपने सभी लक्ष्य पूरे किए हैं जिनमें ईरान की बैलेस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना तथा उसके नाभिकीय कार्यक्रम को बड़ी सीमा तक पीछे धकेलना शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतनयाहू की सरकार ने यह कह कर युद्धविराम को सही ठहराया है कि इसने ईरान द्वारा पैदा किए गए इजरायल के 'अस्तित्व पर दुहरे खतरे' को विफल कर दिया है। दूसरी ओर ईरान सरकार ने इजरायल द्वारा हमले रोकने के निर्णय को दबाव में पीछे हटने वाला कदम बताया है।

तेहरान ने जोर दिया है कि उसकी दृढ़ता तथा जवाबी हमले की क्षमता ने इजरायल को पीछे हटने पर 'मजबूर' किया है, हालांकि अभी उसने अमेरिका द्वारा लागू की गई सारी शर्तें नहीं मानी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह युद्ध भारी राजनीतिक सिर दर्द बन गया था। शुरुआत में उन्होंने इससे अलग रहने का दृष्टिकोण अपनाया, पर बाद में उनको मजबूर हो कर संघर्ष के केन्द्र में आना पड़ा क्योंकि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मध्यपूर्व में अमेरिकन सैनिक अड्डों पर मिसाइलें दागी थीं।

इन तीन देशों का चाहे जो दृष्टिकोण हो, लेकिन यह तथ्य बना हुआ है कि ईरान के मिसाइल हमलों ने इजरायल और उसके आयरन डोम की अजेयता का भ्रम तोड़ दिया तथा उसकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को छिन्न-भिन्न कर दिया। इससे तेलअबीब में यह भय पैदा हो गया कि इजरायल में कोई सुरक्षित नहीं है और वह अमेरिकन हस्तक्षेप की ओर देख रहा है। इजरायल में ऐसे पोस्टर लगने लगे जिनमें ट्रंप से युद्ध समाप्त कराने की अपील की गई थी। इस प्रकार ईरान की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ी। टकराव के शिखर पर उसने हर्मुज जलमार्ग बंद करने का संकेत दिया जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है क्योंकि यहां से दुनिया के तेल का पांचवां हिस्सा गुजरता है। इसकी संभावना ने ही विश्व बाजारों को झकझोर दिया। अमेरिका में, खासकर ट्रंप का राजनीतिक आधार तेल की बढ़ती कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है जिसने प्रकरण को तत्काल समाप्त करने पर जोर दिया। मजेदार बात है कि अमेरिका अपने धुर विरोधी चीन से हस्तक्षेप कर ईरान को यह समझाने को कह रहा था कि वह हर्मुज जलमार्ग बंद करने की योजना छोड़ दे। भारत जो ईरान और इजरायल, दोनों का रणनीतिक साझीदार है अब स्वयं को एक नाजुक पर संभवत: प्रभावशाली स्थिति में पा रहा है। नई दिल्ली की पश्चिम एशियाई तेल पर काफी निर्भरता है और ईरान से उसके लंबे समय से संबंध हैं, जबकि रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में सहयोग के लिए वह इजरायल से सहयोग करता है।

भारत की सक्रिय राजनय ने क्षेत्रीय स्तर पर तनाव घटाने पर जोर दिया है जो पहले के किसी समय की तुलना में आज ज्यादा जरूरी हो गया है। वर्तमान स्थिति में नई दिल्ली संवाद की पैरोकारी कर एक रचनात्मक भूमिका निभा सकती है। इसके लिए वह अपने आर्थिक संबंधों के साथ ही ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों से शांति स्थापना को प्रोत्साहित कर सकती है। यह पूरी दुनिया और खासकर भारत के हित में है कि इजरायल और ईरान के बीच मौजूदा युद्धविराम स्थाई व टिकाऊ शांति की ओर आगे बढ़े।

इजरायल के अस्तित्व पर खतरा

इजरायल जन्म से ही विरोधियों से घिरा है। उसे ईरान की नाभिकीय महत्वाकांक्षा से अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आता है। इसे अनदेखा करना इतिहास, भू-राजनीति और ईरानी नेताओं के भड़काऊ बयानों की अनदेखी होगा।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

इजरायल अपने जन्म के समय से ही विरोधियों से घिरा है। अत: उसे उचित ही ईरान की नाभिकीय महत्वाकांक्षा से अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आता है। इस भय को अनदेखा करना इतिहास, भू-राजनीति और ईरानी नेताओं के भड़काऊ बयानों को अनदेखा करना होगा। पिछले कई दिनों से अनेक विशेषज्ञ और टेलीविजन एंकर कह रहे हैं कि ईरान की नाभिकीय सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमले बिना किसी उकसावे के थे। इन 'विशेषज्ञों' और टीवी पत्रकारों के दृष्टिकोण से ईरान कभी इजरायल के अस्तित्व पर खतरा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इजरायल व खासकर उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने बार-बार अनेक वैश्विक मंचों पर कहा है कि ईरान नाभिकीय हथियार कार्यक्रम विकसित करने की तैयारी कर रहा है और इजरायल उसका एकमात्र निशाना है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यदि ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को नियंत्रित या समाप्त नहीं किया जाता है तो वे उनके देश का अस्तित्व मिटा देंगे।

विशेषज्ञों और पत्रकारों के ऐसे दावों को तथ्यों के आधार पर यथार्थ की रोशनी में देखना जरूरी हो गया है। अनेक अवसरों पर मैंने अनेक एलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया संस्करणों में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनाद्जे को सार्वजनिक रूप से यह कहते सुना है कि इजरायल और यहूदी 'सभ्यता पर अभिशाप' हैं और उनका अस्तित्व देर-सबेर समाप्त करना जरूरी है। अहमदीनाद्जे की ऐसी हिंसक धमकियां उनके राष्ट्रपति पद पर रहने के समय ईरान का इजरायल के प्रति दृष्टिकोण सारी दुनिया के सामने स्पष्ट करने के लिए काफी हैं। अहमदीनाद्जे दो बार इस्लामी गणतंत्र ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। ईरान छोटे से इजरायल की तुलना में बहुत बड़ा देश है जिसका भौगोलिक क्षेत्र मीलों के बजाय मीटरों की नाप में फैला है। 1979 में इस्लामवादियों के कब्जे के पहले ईरान हथियारों से अच्छी तरह लैस था। दूसरी ओर यहूदी शताब्दियों के बाद अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। यहूदियों ने सैकड़ों सालों तक भयानक अत्याचार सहे और अथक संघर्ष कर 1948 में इजरायल के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। इस तथ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ईसाइयत के जन्म के बाद से ही यहूदी खासकर यूरोप में भयानक उत्पीड़न और दमन के शिकार रहे। पूरे मध्य युग में यहूदियों को जमीन रखने तथा सरकारी नौकरियों में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी आजीविका मुख्यत: व्यापार और पैसा कर्ज देने पर निर्भर थी। इसके साथ ही वे चिकित्सा और कानून जैसे पेशों में भी सक्रिय थे। यहूदियों के आत्मविश्वास और उत्साह को उस समय लगभग प्राणघातक हमले का सामना करना पड़ा जब नाजियों ने 'होलोकास्ट' या नस्ली सफाए के द्वारा उनका व्यापक नरसंहार किया।

यह नरसंहार दुनिया में रह रहे हर यहूदी की आत्मा पर भारी बोझ और अस्तित्व पर संकट के रूप में छाया रहा। भले ही दूसरे लोगों के लिए 'एंटी-सेमेटिज्म' या यहूदीवाद-विरोध मामूली अभिव्यक्ति हो, पर यहूदियों के लिए यह अनुभव अत्यधिक विनाशकारी था। अब पश्चिम एशिया में एक और युद्ध तथा इजरायलियों और अमेरिकनों द्वारा ईरान की नाभिकीय सुविधाओं पर हमले के बाद एक देश के रूप में ईरान की जिम्मेदारी सारी दुनिया को यह बताने की है कि उसने इतना जटिल नाभिकीय कार्यक्रम और सुविधायें क्यों बनाई थीं? ईरान की अनेक नाभिकीय सुविधायें जमीन में बहुत गहराई में बनाई गई थीं, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या उनका उद्देश्य सचमुच शांतिपूर्ण था जिसका दावा ईरानी मुल्ला करते हैं? यदि यह नाभिकीय प्रतिरोधक के रूप में थीं तो ईरान को किससे भय था?

ईरान को किससे गंभीर खतरा था? क्या यह रूस, चीन या अमेरिका था? इन नाभिकीय शक्तियों के अलावा दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जिससे ईरान को डरने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने भू-राजनीतिक रूप से वाशिंगटन के खिलाफ मास्को और बीजिंग से गठजोड़ किया था। कहा जाता है कि यदि किसी देश को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हो तो नाभिकीय हथियारों पर अधिकार उसकी वैध राष्ट्रीय इच्छा हो सकती है।

लेकिन ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय निगरानी में है क्योंकि एक देश के रूप में उसने नाभिकीय अप्रसार संधि-एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रकार उसने स्वैच्छिक रूप से नाभिकीय कार्यक्रम से स्वयं को दूर रखा है। अत: उसके अपने अस्तित्व पर संकट का बहाना निरर्थक हो जाता है। उसकी प्रगति-विरोधी व धार्मिक रूप से अंधी सरकार पर शक है कि वह छिपे तौर से शांतिपूर्ण प्रयोग के नाम पर नाभिकीय आयुध कार्यक्रम चला रही थी। ईरान द्वारा सेंट्रीफ्यूज व अन्य नाभिकीय उपकरण प्राप्त करने के प्रयास उसके शांतिपूर्ण नाभिकीय प्रयोग से बहुत आगे जाते थे। उसने दुनिया के अपने नाभिकीय कार्यक्रम के प्रति पैदा इन संदेहों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया था। ऐसे में ईरानी नाभिकीय कार्यक्रम के प्रति इजरायल की आशंका और प्रतिक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति विचारधारा का एकांगी प्रयोग कर अंधा न हो गया हो। 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से ही यहूदी देश को सभी अरब पड़ोसी देशों से भयानक विरोध का सामना करना पड़ा और वे लगातार युद्ध कर उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते रहे।

इससे इजरायल को भी अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए लगातार युद्ध करने पड़े। 1948 के पहले यहूदियों के पास ऐसा कोई देश नहीं था जिसे वे अपना कह सकें। ऐसे में यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उनके लिए अपनी मातृभूमि का क्या महत्व है। दुनिया के अनेक धर्मावलंबियों के अनेक देश हैं और इसलिए उनके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। अपने तकनीकी विकास, बहुत शानदार प्रशिक्षण, सर्वाधिक संवेदनशील अमेरिकन हथियारों तक पहुंच तथा स्वयं अपने बेहतरीन हथियार विकसित करने के कारण इजरायल ने अपने अस्तित्व पर पैदा हर अरब दु:साहस का जवाब दिया। इजरायल के जन्म से लेकर आज तक लगभग यही स्थिति बनी रही।

अरब नेताओं तथा जिहादी इस्लामवादी तत्वों ने कभी इजरायल को नष्ट करने के अपने इरादे छिपाए नहीं। दशकों से 'दुष्ट यहूदीवादी सरकार', 'इजरायल का नाश हो' और 'हम तुमको इस धरती से मिटा कर रहेंगे' जैसी धमकियां लगातार इजरायल को मिलती रहीं। इससे इजरायल को लगातार सतर्क रहना पड़ा और इस प्रक्रिया में वह एक अत्यधिक सैन्यवादी राष्ट्र बन गया। आज भी दुनिया भर के इस्लामवादी और जिहादी तत्व इजरायल का अस्तित्व मिटाने की कसमें खाते हैं। ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनाद्जे के उपरोक्त भड़काऊ बयानों के साथ ही अन्य नेताओं ने भी इजरायल को समाप्त करने के प्रयास किए।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन-पीएलओ के प्रमुख स्वर्गीय यासिर अराफात भी अपने पूरे जीवन भर इजरायल के विरोधी रहे। उन्होंने हमेशा यह डींग हांकी कि 'बहुत जल्दी पूरा येरूशलम फिलिस्तीन राज्य की राजधानी बनेगा।' उनके ऐसे बयान इजरायल और यहूदियों के लिए येरूशलम के महत्व को देखते हुए स्पष्ट रूप से आक्रामक हैं। हर यहूदी के लिए येरूशलम उसके मांस और रक्त की तरह है, बल्कि वास्तव में यह उसका जीवन है। ऐसे में यासिर अराफात समेत अनेक अन्य अरब और इस्लामवादी नेताओं के येरूशलम तथा इजरायल के संबंध में दिए बयान इजरायल के अस्तित्व पर खतरे से कम नहीं हैं।

कुछ अरब देशों ने इजरायल के खिलाफ नाभिकीय आयुध प्राप्त करने के प्रयास भी किए। ईराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन अपने ओसीराक रिएक्टर में ऐसा ही नाभिकीय बम बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसे इजरायल ने 1981 में अचानक हवाई हमला कर नष्ट कर दिया था। इन तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह स्पष्ट है कि 1948 में अपने जन्म के समय से ही इजरायल को स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व पर खतरे का सामना करना पड़ा। ऐसे में वर्तमान समय में कथित 'विशेषज्ञों' और टीवी एंकरों का यह मानना पूरी तरह गलत है कि ईरान से कोई नाभिकीय खतरा नहीं था।

आंतरिक उल्लास में बाधाएं

> सच्चे सुख का स्रोत केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि, यह मन की समता से उत्पन्न होता है।

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

इस संसार में प्रत्येक मनुष्य शाश्वत सुख या स्थायी शांति पाने के लिए आजीवन प्रयास करता है। मनुष्य के कर्म इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निर्देशित होते हैं। लेकिन, सभी प्रयासों के बावजूद, संसार में व्याप्त महान अशांति और उथल-पुथल, व्यक्ति को यह प्रश्न करने पर मजबूर करती है कि, इस सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है? हममें से बहुत कम लोग इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि सच्चे सुख का स्रोत केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि, यह मन की समता से उत्पन्न होता है, यह मन को स्वयं में स्थिर करने से प्राप्त होता है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि मनुष्य का मन अशांत है, तो उसके लिए परोसे गए सबसे अच्छे व्यंजन, उस पर बरसाया गया बड़ा सम्मान और उसका भव्य स्वागत भी उसके लिए बेस्वाद होगा। इसके अलावा, मनुष्य का इन्द्रिय विषयों में लिप्त होना या भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना भी उसे खा जाता है, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि धीरे-धीरे मनुष्य के शारीरिक अंग बेकार हो जाते हैं, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसकी इंद्रियाँ दुर्बल हो जाती हैं, उसका शरीर थक जाता है और क्षीण हो जाता है, उसके जीवन का रस समाप्त हो जाता है और उसका उत्साह और शक्ति समाप्त हो जाती है।

हम यह भी देखते हैं कि एक व्यक्ति को कोई वस्तु बहुत पसंद होती है जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु अभिशाप होती है और वह उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि खुशी भौतिक वस्तुओं पर निर्भर या आनुपातिक नहीं है जिन्हें कोई व्यक्ति संग्रहीत कर सकता है; बल्कि, इसका संबंध व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण और व्यक्ति की आंतरिक

स्थिति से होता है। इसके अलावा, हम देखते हैं कि सांसारिक वस्तुएँ निरंतर बदलती रहती हैं; अपने स्वभाव से ही वे क्षणभंगुर हैं। तो, जो स्थायी नहीं है, वह निरंतर शांति या स्थायी खुशी का स्रोत कैसे हो सकता है? इसके अलावा, हम सभी अपने और दूसरों के अनुभवों से जानते हैं कि मनुष्य अपना पूरा जीवन वस्तुओं को प्राप्त करने, उन्हें संग्रहीत करने, उन्हें उपभोग के योग्य बनाने, फिर उनका उपभोग करने में बिता देता है और यदि अपने पिछले कर्मों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वह इन वस्तुओं को खो देता है, तो यही चीजें मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण का उद्देश्य यह निष्कर्ष निकालना नहीं है कि मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए! जब तक मनुष्य का भौतिक अस्तित्व है, तब तक उसे भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि जैसी चीजों की आवश्यकता होगी और यदि उसके पास ये चीजें नहीं हैं, तो अधूरी भौतिक आवश्यकताएं मनुष्य के मन को परेशान कर सकती हैं।

इसके अलावा, निष्क्रियता धीरे-धीरे आलस्य की ओर ले जाती है जो एक बुराई भी है। तो, उपरोक्त अनुच्छेद में जो व्यक्त किया गया था वह यह था कि केवल वस्तुओं की खोज या धन संचय करने से व्यक्ति को शाश्वत और पूर्ण शांति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। बल्कि, व्यक्ति को अपने जीवन में स्वास्थ्य, मानसिक विश्राम, शांति और अन्य प्राणियों के साथ अच्छे संबंधों की भी आवश्यकता होती है। गहन चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊपर बताए गए चारों प्रकार के सुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं।

जैसा बोओगे, वैसा काटोगे, यह प्रसिद्ध कहावत है। नास्तिकों को भी कर्म के नियम पर विश्वास होना चाहिए क्योंकि यह नियम वैज्ञानिकों द्वारा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में कहे जाने वाले नियम का आध्यात्मिक संस्करण है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, यानी बिना कोई प्रभाव डाले। इसलिए मनुष्य अपने किए गए कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। चाहे कोई संत हो या पापी, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है - यह एक अटल नियम है। इसलिए, कोई भी सही निष्कर्ष निकाल सकता है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए पाप या पापपूर्ण कार्य ही दुख का स्रोत हैं, और इसकी जड़ हमारे मन में है। अनुभव से पता चला है कि योग ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई अपने मन को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि यह मन में मौनता से पैदा होने वाली शांति लाता है। यह मन में निष्क्रियता के रूप में मौजूद दुख के बीजों को नष्ट कर देता है।

योग ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को आनंद मिलता है और उसे इच्छाशक्ति भी मिलती है जिससे उसकी पुरानी आदतें, जो अन्यथा बहुत मुश्किल से छूटती हैं, अब आसानी से और जल्दी छूट जाती हैं। योग मनुष्य को अतीन्द्रिय सुख का एक अक्षय स्रोत प्रदान करता है जो भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है।

यह मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन लाता है और इस प्रकार उसे सभी परिस्थितियों में मन की समता रखने में सक्षम बनाता है।

आप की बात

अंतरिक्ष में भारतीय

अंतरिक्ष में दूसरी बार किसी भारतीय का जाना गर्व की बात है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का क्षण है कि इतने साल बाद एक और भारतीय को अंतरिक्ष यात्रा का अवसर मिला है। इससे पहले 41 वर्ष पूर्व 1984 में राकेश शर्मा ने तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा भेजे अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की थी। इस बार इसरो और नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सहयोग से अंतरिक्ष में प्रवेश हेतु शुभांशु शुक्ला को भेजा गया है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ शहर से हैं जिससे यह पूरा शहर खुशी से झूम रहा है। हालांकि, यह न केवल पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लिए भी गर्व का क्षण है। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल होंगे जिसका लाभ पूरी मानवता के साथ भारत को भी मिलेगा। उनकी यह अंतरिक्ष यात्रा निश्चित रूप से भविष्य में भारत की समानव अंतरिक्ष उड़ान तथा चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने जैसे अभियानों को और गति देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। शुभांशु शुक्ला की यात्रा देश के बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगी जिससे भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप को और तेजी से प्रगति करने का अवसर मिलेगा।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

टीकाकरण पर संकट

चिकित्सा विज्ञान के में बलबूते सन 1940 के दशक से आज तक कई जीवन रक्षक टीके नवजात एवं बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस, खसरा, मम्प्स, रूबेला, पोलियो, हेपिटाइटिस, वैरिसेला, इन्फ्लुएंजा और रोटावाइरस आदि बीमारियों से बचाते रहे हैं। इनमे से अधिकांश टीके, खासकर गरीब देशों में आज भी बच्चो को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बावजूद दुनिया भर में बच्चों में टीकाकरण की दर गिर रही है। इसका कारण आर्थिक असमानता, गलत सूचना और विदेशी सहायता में कटौती है जो दशकों में हुई प्रगति को बाधित कर रहा है। 2023 में दुनिया भर में 1.57 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिन्हे एक भी जीवनरक्षक वैक्सीन नहीं दी गयी। विडंबना है कि दुनिया भर में टीकों पर शोध और विकास के लिए अधिक रकम खर्च की जानी चाहिए, पर इसमें कमी आ रही है। टीका निर्माण के क्षेत्र में निजी दवा कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व व विभिन्न सरकारों द्वारा इस पर खर्च घटाने से करोड़ों बच्चों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। अमेरिका की वर्तमान सरकार के कई मंत्री तो टीकों की अवधारणा से ही सहमत नहीं हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वयं को अलग कर लिया है। यह प्रवृत्ति खतरनाक है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

भारत की रणनीति

डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता केवल अपने स्वार्थ और कारोबार के लिए वैश्विक समीकरण बदलने को तत्पर रहते हैं। खबरें हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख मुनीर के साथ मिलकर अपने बेटों के क्रिप्टो करेंसी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सौदा किया है जिसका एक हिस्सा आतंकवाद को फंडिंग में भी जा सकता है। यह स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। रूस, चीन और भारत के त्रिकोण की प्रासंगिकता अब पहले से कहीं अधिक है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और चीन के रिश्तों में नई नरमी देखी गई जो भविष्य में क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक संकेत हो सकता है। अमेरिका, विशेषकर ट्रंप जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारत को कभी पूरी तरह अपना नहीं मानता। वे भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के बजाय अपने हितों के हिसाब से चलने वाला सहयोगी बनाना चाहते हैं। ऐसे में भारत को चाहिए कि वह किसी गुट में बंधने की बजाय गुटनिरपेक्ष और बहुपक्षीय कूटनीति को अपनाए। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता ही सर्वोत्तम विकल्प है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता वर्तमान बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

अमानवीय अत्याचार

इटावा में भागवत कथावाचक के साथ अमानवीय अत्याचार की घटना सामने आई है। कथावाचक मुकुट मणि यादव की चोटी काटी गई, सर मुंड़वाया गया और एक महिला के पैरों में गिरकर नाक रगड़कर माफी मंगवाई गई। हालांकि, घटना की जांच जारी है और महिला ने कथावाचक द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की है। लेकिन इस घटना से भारतीय समाज में वर्चस्ववादी लोगों की भावना उजागर होती है जिसके चलते वे कुछ जातियों को नीची और कुछ को ऊंची मानते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पीडीए से अत्याचार के मुद्दे की तरह पेश किया है, जबकि प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया है। तथ्य जो भी हों, किसी कामकाज या कथावाचन को किसी जाति से जोड़ कर कथावाचक के साथ अमानवीय अत्याचार को किसी प्रकार सही नहीं ठहराया जा सकता है। इससे समाज में जातीय विभाजन तथा विभिन्न जातियों के बीच घृणा बढ़ने की आशंका है। अगले साल शुरू होने वाली जनगणना व जातीय गणना को देखते हुए ऐसी घटनायें सभी दलों व नेताओं के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए।

- वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
मौन वाणी के उपवास की अवस्था है

नए भारत का कड़ा संदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को साधुवाद कि चीनी प्रभाव वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में वे इस पर अडिग रहे कि यदि आतंकवाद के मामले में दोहरेपन का परिचय दिया जाएगा और संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं होगा तो उस पर भारत की सहमति नहीं होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। ऐसा होना भी भारत की जीत है और चीन, पाकिस्तान समेत विश्व समुदाय को यह सीधा-सख्त संदेश भी कि अब नया भारत अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। संयुक्त बयान जारी न होने से पाकिस्तान और चीन की नीयत भी फिर से उजागर हो गई। चीन को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन वह शायद ही सुधरे। यह एक तथ्य है कि वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षा मंत्री इस पर भी अड़े कि एससीओ में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई दिखाई। इसके कारण ही एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संयुक्त बयान के बिना समाप्त हो गया। इसका संज्ञान तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी लेगा।

यह स्पष्ट है कि एससीओ में चीन-पाकिस्तान के बीच बढ़ते शरारत भरे तालमेल को लेकर भारत को इस संगठन में अपनी भूमिका को लेकर सतर्क होना होगा और चीन में ही होने वाले इस संगठन के शिखर सम्मेलन की अभी से तैयारी करनी होगी। भारत को यह भी देखना होगा कि विस्तार ले रहे इस संगठन में अपनी महत्ता कैसे स्थापित करे। उसे रूस के रवैये का भी नए सिरे से आकलन करना होगा, जो यूक्रेन में उलझे होने के कारण चीन पर अधिक निर्भर हो गया है। यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने रवैये के कारण चीन भारत से संबंध सुधारना चाहता है और कुछ मामलों में अपना रुख बदलने के लिए विवश भी हुआ है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत के हितों की अनदेखी करे या फिर अमेरिका एवं पश्चिम के अन्य देशों की तरह आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए और आतंक के समर्थक पाकिस्तान की पीठ पर हाथ भी रखे रहे। वह अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, लेकिन अभी इसमें सक्षम नहीं। वह और विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति एक तानाशाह ही हैं। भारत को अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए चीन की सहायता तो चाहिए, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करनी चाहिए और गंभीरता के साथ यह देखना चाहिए कि मेक इन इंडिया जैसे अभियान अपेक्षा के अनुरूप सफल क्यों नहीं हो सके?

बायोमीट्रिक बंधन

कल्याणकारी योजनाओं में अनदेखी से उपजी अनियमितता हमेशा भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाती है। ऐसा ही बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हो रहा था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कार्रवाई भी हुई, परंतु धांधली से इतनी पवित्र योजना का उद्देश्य आहत हुआ। बलिया जिले में तो इस योजना में फर्जीवाड़े के दोषी पाए गए लोग काफी संख्या में अब तक जेल में हैं। आश्चर्य है कि दलालों के साथ सरकारी कर्मचारियों की भी संलिप्तता साबित हो चुकी है। जिनको निगरानी करनी थी, वे ही लोभ में लिप्त हो गए। प्रदेश के कुछ अन्य जिलों से भी ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। दलाल के बहकावे में आकर नाबालिग की शादी कराने या पहले हो चुकी शादी फिर से कराने जैसे प्रसंग सामने आए हैं। अभी हाल में ही सुलतानपुर और जौनपुर में भी इसी प्रकार की अनियमितता में कुछ लोगों का अनुदान रोका गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय उचित है कि कन्या के आधार सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। विवाह स्थल पर वर-वधू की बायोमीट्रिक उपस्थिति सहित जिलाधिकारी की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। शादी में सरकारी सहायता और समारोह का प्रशासनिक आयोजन गरीब परिवार की लड़कियों के माता-पिता के लिए बड़ी सहायता है। यह कदम और पहले उठाया जाना चाहिए था। यह सामान्य योजना नहीं है, जिंदगी की डोर बंधने के सपनों को पूरा करने का जतन है। इस योजना के उद्देश्य के अनुरूप ही इसके लाभार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। किसी भी अनुचित व्यक्ति को इसका लाभ न मिले, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए।

> कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने की मुकम्मल व्यवस्था होनी ही चाहिए

भविष्य की आधारशिला रखने वाला मिशन

सृजन पाल सिंह

एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा में एक्सिओम-4 एक मील का पत्थर है

भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन-आइएसएस में दाखिल होकर एक नया इतिहास रचा। वह एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा हैं। यह मिशन नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का समन्वित प्रयास है। इस मिशन के दौरान 60 वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे। इन परीक्षणों में 31 देशों का योगदान होगा, जिनमें सात परीक्षणों में इसरो की सक्रिय भूमिका है। ये परीक्षण माइक्रोबायोलाजी, बायोटेक्नोलाजी, पदार्थ विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे विविध विषयों से जुड़े हैं। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषकों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जाने, प्रवास या अंतरिक्ष में प्रयोग-परीक्षण करने तक ही सीमित नहीं। इसमें उस भविष्य की कुंजी निहित है, जिसमें अंतरिक्ष केवल अन्वेषण का ही एक केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह रणनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे के रूप में भी स्थापित होगा।

यह स्पष्ट है कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष भूराजनीति, वैश्विक शक्ति समीकरण और आर्थिक वृद्धि को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। चाहे उपग्रह संचार से लेकर रक्षा प्रणालियों का मामला हो या संसाधन उत्खनन से अंतरिक्ष पर्यटन का विषय, उनमें देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं ही यह निर्धारित करेंगी कि कौन देश इसमें बढ़त बनाएगा और कौन अनुसरण करेगा। अंतरिक्ष में नियंत्रण का अर्थ है संचार पर नियंत्रण? यह स्थिति युद्ध और टकराव में बहुत उपयोगी साबित होती है। सैटेलाइट नेटवर्क की महत्ता तो सैन्य संचार से लेकर रियल टाइम नेविगेशन और जलवायु निगरानी के मोर्चे पर पहले ही सिद्ध हो चुकी है। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका उदाहरण है। जब रूस ने यूक्रेन के संचार ढांचे को तबाह कर दिया तब एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सुविधा ही यूक्रेन के काम आई।

आधुनिक समर नीति में भी अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है। सशक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देशों को स्वाभाविक रूप से सामरिक बढ़त मिलती है। ईरान-इजरायल के हालिया युद्ध में भी इसका प्रमाण दिखा, जहां ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल के एयरो-3 डिफेंस सिस्टम ने पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर ही निष्प्रभावी कर दिया। यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कैसे आधुनिक समर नीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बीते दिनों भारत के आपरेशन सिंदूर में भी सैटेलाइट कैमरों की उपयोगिता दिखी, जिन्होंने लक्ष्यों को चिह्नित करने और नुकसान के आकलन में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्पेस फोर्स नाम से एक अलग सैन्य इकाई का गठन किया है। भारत भी इस संकल्पना को साकार करने जा रहा है।

अवधेश राजपूत

आर्थिक मोर्चे पर भी अंतरिक्ष नया अखाड़ा बन रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन अब कोई कपोल-कल्पना नहीं। कुछ कंपनियों-संगठनों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसरो भी इस दिशा में काम कर रहा है और उसकी 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की योजना है। 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन कारोबार के 85,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

चूंकि भारत की पहचान विश्वसनीय और किफायती प्रक्षेपण क्षमताओं वाले देश की है, इसलिए यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस बाजार में उसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होने वाला है। विस्तार ले रही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वही देश बाजी मारने में सफल हो सकते हैं, जो मनुष्यों से लेकर मशीनों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होंगे। ऊंचे दांव वाली इस होड़ में भारत बिल्कुल सटीक मौके पर कदम बढ़ा रहा है। एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा में एक्सिओम-4 मिशन एक मील का पत्थर है। सीधे तौर पर इसका सरोकार भारत के गगनयान कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत स्वदेश निर्मित यान के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की योजना है। यह 2027 तक संभव हो सकता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन-बीएएस के रूप में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। यह केंद्र शोध-अनुसंधान, नवाचार एवं लंबी अवधि वाले मिशन के लिए एक मंच की भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में स्थायी मानवीय उपस्थिति वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। एक्सिओम-4 मिशन के दौरान लाइफ साइंस, कक्षीय परिचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मोर्चे पर सीखे जाने वाले सबक बीएएस के डिजाइन और संचालन ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अंतरिक्ष में मूल्यवान संसाधनों का भंडार भी छिपा है। इस संदर्भ में मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह (एस्टेरायड) बेल्ट सर्वाधिक संपन्न है। इनमें प्लेटिनम, सोना, कोबाल्ट, लीथियम जैसे वैसे दुर्लभ संसाधन हैं, जो बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक जैसी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी पर सिकुड़ते संसाधनों को देखते हुए भविष्य की आर्थिकी में अंतरिक्ष खनन का महत्व बढ़ेगा। समझ लीजिए कि संपूर्ण विश्व का सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी करीब 100 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर है तो केवल क्षुद्रग्रह बेल्ट की हैसियत ही दुनिया के उत्पादन से करीब 8,000 गुना अधिक है। यानी वहां मौजूद खनिजों का मूल्य इतना अधिक है कि पूरी दुनिया अगली 80 शताब्दियों तक कमाई के जरिये ही उसकी बराबरी कर पाएगी। जो देश इन इलाकों में सबसे पहले पहुंचकर उसके कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, वही भविष्य के उद्योगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के चक्र को नियंत्रित कर सकेंगे। वे कीमतों के निर्धारण, नए उद्यमों की स्थापना और वैश्विक बाजारों को आकार देंगे। यही वजह है कि अंतरिक्ष में पैठ भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं और महारत से भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी और प्रशिक्षण के जरिये अंतरिक्ष में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व कर सकता है। यह रणनीति कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण को भी कहीं अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत बनाएगी।

(पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं)

response@jagran.com

दम तोड़ते दिख रहे माओवादी

उमेश चतुर्वेदी

मोदी सरकार को इससे सावधान रहना होगा कि माओवाद के वैचारिक समर्थक शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं

हर शासक का असल मूल्यांकन इतिहास करता है। मोदी सरकार का भी करेगा। लोकतांत्रिक भारत की सत्ता के केंद्र अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बने हुए हैं, तो इसकी वजह उनकी कई उपलब्धियां भी हैं। मोदी के शासन की सफलताओं में से एक है देश से वामपंथी उग्रवाद का लगभग सफाया। मोदी सरकार माओवादी आतंक के खात्मे के लक्ष्य पर शुरू से ही काम करती रही है, लेकिन अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद इसमें तेजी आई है। इसका असर अब दिखने लगा है। माओवादियों के पांव उखड़ रहे हैं, वे सरेंडर करके सामाजिक मुख्यधारा में लौट रहे हैं, लेकिन सियासी जुबान में माओवाद की गूंज सुनाई देती रहती है। पहले नक्सली कहे जाने वाले माओवादी भी अभी पूरी तौर पर पस्त नहीं हुए हैं। उनसे वैचारिक स्तर पर भी लड़ने की जरूरत है।

1925 में विरोधी वैचारिक छोर पर खड़े दो संगठनों का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद के ध्येय के साथ विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ तो लगभग तीन माह बाद दिसंबर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सौ वर्षों की यात्रा में कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर होता गया, जबकि संगठन और विचार के स्तर पर संघ विराट वृक्ष बन चुका है। आजादी के बाद ही आंध्र प्रदेश में हथियारबंद कथित कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हो गई थी, लेकिन इसे गति 1970 के दशक की शुरुआत में बंगाल के नक्सलबाड़ी से मिली। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग का कहना था कि सत्ता बारूद से निकलती है। नक्सल आंदोलन ने दो तरह से अपना प्रभाव बढ़ाया। शैक्षिक संस्थानों और वैचारिक प्रतिष्ठानों में इस वैचारिकी ने बौद्धिक जड़ें जमाईं तो दूसरी तरफ खेतों और जंगलों में खूनी क्रांति का सपना पूरा करने के लिए नौजवान हाथों ने हथियार थाम लिए। धीरे-धीरे वैचारिक प्रतिष्ठानों में इस विचार का वैचारिक प्रभाव तो बढ़ा ही, जंगलों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों में हथियारबंद संगठनों का असर बढ़ा। हथियारबंद आंदोलन की पहले जो नक्सलबाड़ी पहचान थी, उसे माओवादी के रूप में जाना जाने लगा। जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में हथियारबंद आंदोलन जहां खूंखार होता गया, वहीं उसे वैचारिक कवच वैचारिक प्रतिष्ठानों के बौद्धिकों से मिलने लगा। वैचारिक प्रतिष्ठानों में माओवाद समर्थक लोग तत्कालीन सत्ता का विरोध करते हुए भी सत्ता प्रतिष्ठानों के आदरणीय बने रहे, जबकि हथियारबंद दस्तों ने सत्ता के खिलाफ खूनी संघर्ष जारी रखा। एक दौर में छत्तीसगढ़, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर उनका असर हो गया।

माओवादियों से लोहा लेने वालों के संग अमित शाह। प्रेट्र

मोदी सरकार के सत्ता संभालते वक्त देश के लगभग एक चौथाई जिलों में लाल आतंक कायम था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार अब महज 18 जिलों में ही माओवाद का प्रभाव है। माओवाद कितना दुस्साहसी है, इसका अंदाजा दो घटनाओं से लगाया जा सकता है। माओवादियों ने 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को विस्फोट से उड़ाकर तत्कालीन सत्ता को चुनौती दे डाली थी। इसके तीन साल बाद छत्तीसगढ़ की ही दरभा घाटी में माओवादियों ने घात लगाकर राज्य कांग्रेस के करीब-करीब पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया था। ताड़मेटला की घटना से क्रुद्ध मनमोहन सरकार ने जंगलों में छिपे माओवादियों पर हवाई कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, पर शहरों के वैचारिक प्रतिष्ठानों में काबिज उसके वैचारिक दस्तों के प्रबल विरोध के चलते उसे पीछे हटना पड़ा था। चाहे हथियारबंद माओवादी दस्ते हों या शहरी प्रतिष्ठानों की माओवाद समर्थक वैचारिकी, दोनों के निशाने पर संघ और भाजपा रहे हैं।

2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा ने जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया, उसमें माओवादी हिंसा को खत्म करने का भी लक्ष्य तय किया गया था। माओवादी हिंसा के चलते आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति धीमी पड़ी। इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में हथियारबंद दस्तों का प्रतिरोध बड़ी बाधा रहा। माओवादी अक्सर स्कूलों, पंचायत भवनों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों आदि को निशाना बनाते रहे हैं। मोदी सरकार ने माओवाद के खात्मे के लिए दो मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। हथियार उठाने वालों के लिए जहां गोली का जवाब गोली से देने की नीति अपनाई, वहीं माओवादियों के सरेंडर और उनके सामाजिक पुनरुत्थान पर जोर दिया। पिछड़े इलाकों में सड़कें और रेलवे लाइन पहुंचाई गईं। मोदी सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूल बनाने और विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया। सरकारी नीतियों को लागू करने और माओवादी हथियारबंद दस्तों के खिलाफ कार्रवाई में हाल में काफी तेजी आई है।

एक तरफ जहां माओवादी हिंसा पर लगाम लग रही है, वहीं सियासी वैचारिकी में माओवाद का विस्तार होता दिख रहा है। राहुल गांधी एक बार यह कह चुके हैं कि वह भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यही भाषा माओवादियों की भी है। जिस कांग्रेस के छत्तीसगढ़ नेतृत्व का माओवाद ने खात्मा कर दिया था, उसी कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 'नक्सल आंदोलन' को सामाजिक आंदोलन बता रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की वापसी कहीं दिख नहीं रही, लेकिन कुछ मामलों में उनकी और कांग्रेस की भाषा एक सी रहती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आस्था का प्रभाव

आस्था में असीम ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान करती है। किसी के प्रति अथाह विश्वास-निष्ठा ही आस्था कहलाती है। प्रायः हम आस्था को धर्म-कर्म से जोड़ लेते हैं। इसका संबंध केवल धर्म-कर्म, अध्यात्म या ईश्वर के संबंध तक ही सीमित करना उचित नहीं होगा। आस्था बहुआयामी है। ईश्वर पर आस्था हमारे लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मार्ग हमारा सत्य, अहिंसा एवं परमार्थ से साक्षात्कार कराता है। ईश्वर पर आस्था ही हमें संकटों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। इसी तरह जब प्रकृति पर गहरी आस्था होती है तो हमारा हृदय उदारता से भरने लगता है। हम सहिष्णु होने लगते हैं। हम स्वयं से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि यही प्रवृत्ति वास्तव में प्रकृति की होती है। प्रकृति हमें सबकुछ निःस्वार्थ भाव से ही देती है। नदियों का जल, पेड़ों के फल, पुष्प और झरने सब परमार्थ के लिए ही तो होते हैं। प्रकृति पर आस्था ही हमें इन सब ईश्वरीय गुणों का सामीप्य प्रदान करती है।

जब हमारी आस्था अपने गुरु पर होती है तब हम अपने क्षेत्र में सिरमौर बन जाते हैं। फिर यह मायने नहीं रखता कि गुरु प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हैं अथवा नहीं। बस उनके प्रति समर्पण ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे ज्ञान चक्षु खोलता है। हमें अभिनव सामर्थ्य से आप्लावित कर देता है। यही आस्था जब माता-पिता पर होती है तो हम श्रवण कुमार बन जाते हैं। माता-पिता की हर इच्छा की पूर्ति के लिए सब कुछ करने लगते हैं। उनका आशीर्वाद कृपा के रूप में बरसने लगता है।

इस प्रकार, आस्था की शक्ति के बल पर हम जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं। जीवन को नए आयाम दे सकते हैं। हमारी आस्था हमारी उन्नति का कारण बन सकती है। बस हमें आस्था के सही केंद्र की खोज करनी होगी। हमारी सही खोज ही हमारे जीवन को सुवासित कर सकती है।

ललित शौर्य

डिजिटल जिम्मेदारी भी समझें युवा

ऋत्विक कैलाश श्रीवास्तव

> तकनीक का उपयोग सही दिशा में हो तो वह वरदान है, पर जब वह नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो जीवन पर बोझ बन जाती है

आज के दौर में तकनीक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने जहां लोगों को जानकारी, सुविधा और मनोरंजन के अनेक साधन दिए हैं, वहीं कुछ ऐसे खतरे भी पैदा हुए हैं जिनका असर सबसे अधिक हमारे युवाओं पर हो रहा है। इन्हीं में से एक है आनलाइन गेमिंग। आज अधिकांश युवा मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं। जिससे बाहर की दुनिया से उनका रिश्ता धीरे-धीरे टूटने लगता है। दरअसल आनलाइन गेम्स बनाए ही ऐसे जाते हैं कि वे खेलने वाले को बार-बार लौटने के लिए प्रेरित करें। एक स्तर पार करने के बाद नया स्तर, नए इनाम और प्रतियोगिता की भावना युवा मन को बांधे रखती है। धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और फिर लत में बदल जाती है।

कई संस्थाओं द्वारा की गई रिसर्च इस बात की पुष्टि करती है कि आनलाइन गेमिंग की लत से बच्चों और किशोरों में मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी और एकाग्रता की समस्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिरदर्द, पीठ व गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। कई छात्र कक्षाओं में ध्यान नहीं दे पाते, परीक्षा में कम अंक लाते हैं और आत्मविश्वास खो बैठते हैं। गेम में हारने पर गुस्सा आना, चिंता होना और दूसरों से बहस करना एक आम स्थिति हो गई है। यह धीरे-धीरे अवसाद या तनाव में बदल सकता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चे ने पढ़ाई तक छोड़ दी। यह न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है।

इस समस्या का समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था से नहीं होगा। इसके लिए घर, स्कूल और समाज को एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। माता-पिता बच्चों के साथ समय बिताएं। गेम की जगह खेलकूद, संगीत या रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मोबाइल का समय तय करें और निगरानी रखें। शिक्षकों और स्कूल की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों को समय प्रबंधन और डिजिटल अनुशासन सिखाया जाए। काउंसलिंग से बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत किया जाए। साथ ही, युवाओं को स्वयं भी यह समझना होगा कि गेम मनोरंजन का माध्यम हो सकता है, जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन में सफलता के लिए पढ़ाई, मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जरूरी है।

आनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसान को समझ सामूहिक जागरूकता फैलानी होगी और ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें युवा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करें। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं, जिसमें डिजिटल आजादी के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी सिखाई जाए, ताकि हमारा युवा वर्ग एक मजबूत, स्वस्थ और संतुलित भविष्य की ओर बढ़ सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

शिक्षा क्षेत्र को चाहिए और सुधार

प्रणव कुमार का आलेख 'उच्च शिक्षा में कुछ अच्छा होता हुआ' उच्च शिक्षा के मोर्चे पर नए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में से 112 में से 54 ने क्यूएस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिसमें 2014 में केवल 11 संस्थान ही शामिल थे। इन संस्थानों ने शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया होगा तभी सफल हुए हैं। हालांकि यह अभी भी चिंता का विषय है कि इस विश्व रैंकिंग में सफलता मुख्यतः आइआइटी, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों और चुनिंदा संस्थानों तक सीमित है। हमारे देश के अन्य विश्वविद्यालय क्यों पिछड़े हैं? इस पर भी समग्रता में विचार किया जाना चाहिए। इसके कुछ कारण समझ आते हैं। जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती, जिससे शोध और विकास कार्य में बाधाएं आती हैं। इसे दूर करना आवश्यक है। शोध-अनुसंधान में कमी के कारण भारतीय संस्थान नवीनतम ज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीछे रह जाते हैं। इसके लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान देना होगा। आधुनिक तकनीक वाली प्रयोगशालाओं के अभाव में छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान में कमी आती है। इसके लिए निवेश की आवश्यकता है।

डा. प्रदीप कुमार संघवी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, झाबुआ (मप्र)

मेलबाक्स

चुनाव में धांधली पर आयोग का संज्ञान

किसी भी राज्य में चुनाव हो और अगर कांग्रेस पार्टी की वहां हार हुई है तो अक्सर ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी एवं उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने किसी न किसी बात को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची सहित अन्य कई दूसरी चुनाव संबंधी गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उसके कई नेताओं सहित स्वयं राहुल गांधी पिछले कुछ समय से निरंतर राज्यों की विधानसभा में अपनी पार्टी की हार को लेकर चुनाव आयोग पर कुछ न कुछ आरोप लगाते रहे हैं। वैसे तो इन आरोपों का जवाब देने का चुनाव आयोग ने प्रयास भी किया है। परंतु कांग्रेस पार्टी तो चुनाव में धांधली को लेकर न्यायालय तक गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार आयोग की शिकायतों को लेकर अब चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी एवं उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अपनी ओर से एक न्योता दिया है जिसमें उसने राहुल गांधी को चुनाव संबंधी हर तरह की शिकायतों को लेकर आयोग के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। आशा की जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी अपनी चुनाव संबंधी आकांक्षाओं के समाधान के लिए आयोग के न्योते को स्वीकार करेंगे।

मनमोहन राजावत, शाजापुर

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सभी जिलों में संभावित दुर्घटना क्षेत्र की पहचान करते हुए सुरक्षा के उपाय सुझाए गए हैं। परंतु इनके समुचित क्रियान्वयन पर शासन तंत्र की सुस्ती नहीं टूट रही है, जो 'चिंताजनक कार्यशैली' को इंगित करता है। तंत्र को सड़क हादसे रोकने के लिए अपनी सुस्ती का त्याग करना बहुत जरूरी है। यह तंत्र की जवाबदेही है कि सुरक्षा के पुख्ता उपाय करे। सुरक्षा उपाय करने की जवाबदेही जनता ने सरकार को चुनकर उसके हाथों में दे रखी है। जब सुरक्षा के उपाय सुझाए गए हैं तो उन्हें क्रियान्वित करने में अनदेखी करना सरकार की अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। पूरे देश के सभी राज्यों में सड़क हादसे चिंतित करने वाले हैं। परंतु न तो वाहन चालक सबक ले रहे हैं, और न ही तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिख रहा है। सड़क हादसों पर चिंता करते हुए सभी प्रदेशों की सरकारों को आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, ... प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

192 अमेरिकी विश्वविद्यालयों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में स्थान प्राप्त हुआ है, जो इस मामले में पहले नंबर पर है। इस मामले में दूसरे नंबर पर यूके (90) और तीसरे स्थान पर चीन (72) है, जबकि भारत (54) चौथे स्थान पर है।

आजकल

वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने की राह पर देश

कैलाश बिश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

जब कोई देश शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाता है, तो उसका असर परीक्षा परिणामों पर भी दिखता है। साथ ही, वैश्विक मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थानों का शामिल होना इसी सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। एक दशक पहले जहां मात्र 11 संस्थान इस सूची में थे, आज उनकी संख्या पांच गुना बढ़कर यह संकेत दे रही है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता और नवाचार के रास्ते पर आगे बढ़ रही है

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस वर्ष भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थानों को इस वैश्विक सूची में स्थान मिला है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। खास बात यह है कि इन संस्थानों में तकनीकी संस्थान, शोध-केंद्रित विश्वविद्यालय और नवाचार को बढ़ावा देने वाले परिसर शामिल हैं, जिससे यह सफलता केवल संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आइआइटी दिल्ली का 123वें स्थान पर पहुंचना और आठ नए संस्थानों का पहली बार सूची में आना यह बताता है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली आत्मविश्वास के साथ अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर खड़ी हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे सबसे बड़े प्रतिनिधि देश के रूप में भारत की यह स्थिति न केवल गर्व की बात है, बल्कि आने वाले वर्षों में यह युवाओं के लिए नए अवसरों और दिशा का संकेत भी है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) में लचीलापन, रिसर्च को प्राथमिकता, इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम और संस्थानों की स्वायत्तता जैसे बदलावों पर जोर दिया। इसी के साथ योजनाएं जैसे- इंप्रिंट (शोध के लिए मिशन मोड), स्पार्क (वैश्विक साझेदारी), रूसा (राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा सुधार) और स्टार्स (उच्च गुणवत्ता के लिए मूल्यांकन प्रणाली) ने शैक्षिक संस्थानों को मजबूती दी। एक और खास बात यह है कि भारत के 48 प्रतिशत ऐसे संस्थानों ने, जो इस साल की रैंकिंग में शामिल हैं, अपनी स्थिति में पिछले साल की तुलना में सुधार किया है।

हालांकि, सभी क्षेत्रों में भारत की स्थिति समान रूप से मजबूत नहीं है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात और संकाय-छात्र अनुपात जैसे मानकों पर भारत अभी पीछे है। क्यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक, 78 प्रतिशत भारतीय संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या घटी है। फैकल्टी/ छात्र अनुपात में 63 प्रतिशत भारतीय विश्वविद्यालयों में गिरावट देखी गई, जो एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती है। ये संकेत करते हैं कि हमें शिक्षा को केवल घरेलू जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि वैश्विक मानकों के अनुसार तैयार करने की दिशा में और प्रयास करने होंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। वर्ष 2023-24 में यह संख्या करीब 15 लाख थी, जो 2024-25 में 18 लाख तक पहुंच गई।

भारत जैसे विशाल देश में यह संख्या भले ही ज्यादा नहीं लगती हो, लेकिन एक बात साफ है कि विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं का बेहतर प्रदर्शन न कर पाना भी इसकी एक महत्वपूर्ण वजह रही। इन तमाम उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अब बदलाव के मोड़ को पार कर चुकी है। अब यह केवल डिग्री बांटने वाली व्यवस्था नहीं रही, बल्कि विचार, शोध और नवाचार की जमीन बन चुकी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 केवल एक सूची नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की गवाही है जो पिछले एक दशक में भारत की शिक्षा नीति और संस्थानों ने मिलकर रचा है।

चुनौतियां : भारत में एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय और 42 हजार से अधिक महाविद्यालय हैं। फिर भी सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) केवल 27.1 प्रतिशत है। मुख्य समस्याएं हैं- अंक आधारित प्रणाली, अनुसंधान की अनदेखी, सरकारी हस्तक्षेप, योग्य शिक्षकों की कमी, निवेश की कमी और छात्रों का ड्रापआउट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वायत्तता, उद्योग और समाज के साथ तालमेल पर बल देना होगा। देश के हजारों कालेज और विश्वविद्यालय अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां वैश्विक रैंकिंग में उनकी चर्चा हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा केवल कुछ संस्थानों की चमक से नहीं, बल्कि समग्र व्यवस्था की मजबूती से बनती है। शहरों के बाहर, ग्रामीण इलाकों में और हिंदी माध्यम जैसे क्षेत्रों में अभी बहुत काम बाकी है। फिर भी, भारत की यह छलांग साफ तौर पर दिखा रही है कि हम दिशा सही पकड़ चुके हैं। अब जरूरत है इस गति को बनाए रखने की, और यह सुनिश्चित करने की कि शिक्षा केवल रैंकिंग तक सिमटी न रहे, बल्कि हर विद्यार्थी के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बने। भारतीय पाठ्यक्रम अक्सर उद्योग की जरूरतों से कटा रहता है। कैरियर परामर्श और रोजगारपरकता भी एक क्षेत्र है जिसमें भारतीय संस्थान अपने विदेशी समकक्षों से बहुत पीछे हैं। हमारा पाठ्यक्रम उन लोगों से चर्चाओं पर आधारित नहीं होता है जो अंततः हमारे छात्रों को रोजगार देते हैं या अपने यहां काम पर रखते हैं।

आगे की राह : विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने संकाय, छात्रों और उद्योगों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दें, ताकि शोध केवल थ्योरी नहीं रहे, बल्कि समाज की जरूरतों से जुड़ा हो। विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय उद्योगों से साझेदारी करनी चाहिए। इससे न केवल रिसर्च फंड मिलेगा, बल्कि छात्रों को इंटर्नशिप और रोजगार के अच्छे मौके भी मिलेंगे। इसी तरह, आनलाइन डिग्री प्रोग्राम और उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स बनाकर वैश्विक छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है। इससे प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही आर्थिक संसाधन भी मजबूत होंगे।

वहीं दूसरी ओर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक परिसरों में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करनी होगी। जब छात्र नए विचारों पर काम करते हैं और उन्हें हौसला मिलता है, तो विश्वविद्यालय नवाचार के केंद्र के रूप में उभरता है। आज के विश्वविद्यालयों को समाज से भी जुड़े रहना होगा। पाठ्यक्रम में ऐसे प्रोजेक्ट शामिल होने चाहिए जो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करें। इससे छात्रों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर अगर हम शिक्षा को नवाचार, समावेश और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ें, तो हमारे विश्वविद्यालय न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी नेतृत्व कर सकते हैं।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आइआइटी दिल्ली ने 123वां स्थान प्राप्त किया है जो देश के लिए गर्व का विषय है। फाइल

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की नई दिशा

भारत में उच्च शिक्षा का तंत्र आकार और विविधता की दृष्टि से बहुत विशाल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। देश में चार करोड़ से अधिक छात्र उच्च शिक्षा में नामांकित हैं, जो दुनिया के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इस तंत्र में आइआइटी, आइआइएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी संस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ओपन यूनिवर्सिटी जैसे विविध संस्थान शामिल हैं, जो इसे एक जटिल, लेकिन प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करते हैं। परंतु इस बड़े आकार और विविधता के बावजूद भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है- गुणवत्ता की कमी।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि सरकार जब भी कोई नीति बनाए, तो वह इस पूरे तंत्र की विविधता और व्यापकता को ध्यान में रखे। भारत जैसे देश में एक ही नीति से सबका भला नहीं हो सकता। बड़े और छोटे, ग्रामीण और शहरी, विज्ञान और कला आधारित, सरकारी और निजी-इन सभी संस्थानों की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। राज्यों की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों की भर्ती और डिग्री निर्धारण जैसी बातों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्वयं को बेहतर बना सकें। सरकार को विश्वविद्यालयों के साथ अविश्वास के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में काम करना चाहिए।

अनुसंधान और नवाचार उच्च शिक्षा के आत्मा होते हैं। परंतु भारत में कई उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके पीछे प्रमुख कारण है- अनुसंधान में अपर्याप्त फंडिंग। सरकार को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए। खासकर सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषय, जो अक्सर तकनीकी शिक्षा के सामने उपेक्षित रह जाते हैं, उन्हें भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। सरकारी संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है, जो वित्तीय अनुपालन की निगरानी करे और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करे। इसके अतिरिक्त, सरकारी संस्थानों को धीरे-धीरे वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना चाहिए।

एक बड़ी आवश्यकता यह भी है कि शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित संस्थानों की स्थापना एवं संचालन शिक्षाविदों, विज्ञानियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा होनी चाहिए, न कि राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा। शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें गहराई, संवेदनशीलता और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो केवल विशेषज्ञों के माध्यम से ही संभव है। यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में केवल राजनीतिक लाभ देखा जाएगा, तो गुणवत्ता का ह्रास तय है। आज जो सबसे बड़ा खतरा है, वह यह कि कई बार नीति निर्माता निर्णय लेने से कतराते हैं, क्योंकि निर्णय लेने से आलोचना हो सकती है। किंतु यह भी सही है कि सही दिशा में साहसिक निर्णय न लेना ही सबसे बड़ी विफलता है।

अंततः भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए उसे अधिक से अधिक स्वायत्तता, विविधता और गुणवत्ता-आधारित प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाना होगा। सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप कम किया जाए और संस्थानों को अपनी पहचान, संस्कृति और नवाचार के लिए स्वतंत्रता दी जाए। यदि भारत को विश्वगुरु बनने का सपना साकार करना है, तो उसकी नींव उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में ही रखी जानी चाहिए, जो केवल डिग्री देने तक सीमित न हो, बल्कि सोचने, खोजने और सृजन करने की क्षमता दे।

(कैलाश बिश्नोई)

फिर से

स्त्रियों के उत्पीड़न से बचाव की पहल

यौन उत्पीड़न के संदर्भ में लोग आजकल खुलकर बहुत कुछ लिखते और बोलते हैं। इंटरनेट मीडिया ने इसे एक नया पंख लगा दिया है। इससे संबंधित घटनाक्रमों से जुड़े कंटेंट से इंटरनेट मीडिया भरा हुआ है। परंतु इस प्रसंग में स्त्री और पुरुष के लिखने में जो अंतर है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे भी बहुत कुछ साफ होता है। दरअसल पुरुष उस यातना को कभी समझ नहीं सकते, जिससे कोई पीड़ित स्त्री गुजरती है। यह किसी एक घटना से नहीं होता। इसे समझने के लिए एक स्त्री का जीवन चाहिए, जो किसी मर्दपरस्त समाज में शुरू से अंत तक यातना के दौर से गुजरता है।

सर्वाइवर यानी पीड़िता को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह अपनी लड़ाई किस तरह लड़ना चाहती है। कम से कम पुरुषों को उसे सही तरीका सिखाने से बाज आना चाहिए। यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा की बुनियाद है चहुंओर फैला हुआ स्त्री विद्वेष। विडंबना यह है कि तुलनात्मक रूप से संवेदनशील वर्गों में भी रंग भेद और जाति विद्वेष के विरुद्ध जैसा आक्रोश है, वैसा स्त्री विद्वेष को लेकर नहीं।

हमारे समाज में स्त्री विद्वेष की अक्सर अनदेखी की जाती है, उसे बर्दाश्त किया जाता है और अक्सर उसे प्रदर्शित करने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। यही है वह माहौल जिसमें उत्पीड़न आसान और लगभग सुरक्षित हो जाता है। इस वातावरण को बदलना चाहिए।

ऐसे में नई धारा के हिसाब से लिखने वाले लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह चर्चित प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लें। सर्वाइवर की निजता भंग किए बगैर उस घटना की जांच करनी चाहिए और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। आरोपों की सच्चाई स्थापित होने पर न्याय के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। अन्यथा सब पहले की तरह चलता रहेगा। नई पहल के साथ आगे बढ़ा जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है।

(आशुतोष कुमार की फेसबुक वाल का संपादित अंश, साभार)

पोस्ट

प्यारे देशवासियो वाला संबोधन तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस संबोधन में जो बात है वह और कहां। कैप्टन शुक्ला ने देशवासियों को इन्हीं गौरवपूर्ण शब्दों से संबोधित किया। जय हिंद।

प्रभाकर मिश्रा@PMishra_Journo

आतंक के साथ समझौते का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इस मुद्दे पर यही रुख अपनाया जा सकता है, जो रक्षा मंत्री ने अपनाया। जय हिंद।

केजेएस ढिल्लो@TinyDhillon

चीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह फटकार याद रखेगा कि 'आतंकवाद के साथ शांति का कोई सह-अस्तित्व नहीं हो सकता।' नया भारत घर में घुसकर ललकारता भी है।

अनुपम के. सिंह@anupamnawada

हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने के बाद पानी के साथ लकड़ियों का जो सैलाब आ रहा है, वह दर्शाता है कि राज्य में कितने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। किसी के मन में अगर वर्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर सवाल उठ रहा हो तो इसका जवाब इसी पहलू में छिपा है।

निखिल सैनी@iNikhilsaini

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दो बार कराने का फैसला सही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या एससीओ में भारत के कड़े रुख से आतंकवाद के खिलाफ चेहराफन बदहोगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लालू भैया शान से बने पुनः अध्यक्ष,
क्योंकि दल में है नहीं कोई इतना दक्ष।
कोई इतना दक्ष कभी ना कहते 'नाहीं',
लोकतंत्र के नाम चल रही राजशाही!
दल के बाकी लोग ढूंढेंगे मैसी-मैया,
निर्विरोध अध्यक्ष रहेंगे लालू भैया!!

\- ओमप्रकाश तिवारी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

धधक रहे झरिया में पुनर्वास की नई उम्मीद

दशकों से भूमिगत आग की चपेट में आकर धधक रहे झरिया की तकदीर अब बदलने वाली है। यहां आग के ढेर के ऊपर हजारों की आबादी अपनी जान जोखिम में डालकर रह रही है। उनके पुनर्वास की योजना बहुत सुस्त रफ्तार से चली और प्रभावितों ने भी एक जगह से हटकर दूसरे जगह जाने में कम रुचि दिखाई। इस बीच योजना की लागत भी बढ़ती चली गई और प्रभावितों की संख्या भी। अब केंद्र सरकार ने यहां के 14,569 प्रभावित परिवारों के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों में नई उम्मीद जगी है। इसका कट आफ डेट भी 2004 से बढ़ाकर 2019 कर दिया गया है। इससे अब ज्यादा प्रभावितों को पुनर्वास का लाभ मिल सकेगा।

कोयला उत्पादन के माध्यम से देश को रोशन करने वाले झरिया के लोगों की जिंदगी आग के कारण अंधेरे में ही रहती आई है। अब उन्हें नई रोशनी दिख रही है। मोदी सरकार भूमिगत आग से निपटने और इससे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर 5,940 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राष्ट्रीयकरण के बाद झरिया में कोयले में आग की समस्या के अध्ययन के लिए सबसे पहले वर्ष 1978 में एक विशेषज्ञ दल बनाया गया था। इसकी जांच में पता चला कि उस वक्त बीसीसीएल की 41 कोयला खदानों में आग की 77 घटनाएं हुई थीं। केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में झरिया कोयला क्षेत्रों में आग और जमीन धंसने की समस्याओं की व्यापक समीक्षा के लिए कोयला सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।

कहा जाता है कि झरिया कोलफील्ड में संचालित कोयला खदानों में आग लगने की पहली घटना 1916 में सामने आई। उसके बाद से खदान में कोयले भंडार से ऊपर की सतह में कई बार आग लग चुकी है। राष्ट्रीयकरण के समय झरिया कोयलांचल के करीब 17.32 वर्ग किमी में आग फैली हुई थी, लेकिन यह अब करीब 1.53 वर्ग किमी क्षेत्र में सिमट गई है। राष्ट्रीयकरण होने से पहले खदानें निजी स्वामित्व में थीं। लाभ के कारण लोगों के जानमाल की परवाह भी निजी कंपनियां नहीं करती थीं। खनन भी अवैज्ञानिक तरीके से करती थीं। सुरक्षा, संरक्षण और पर्यावरण की चिंता भी नहीं करती थीं। इस कारण झरिया में जमीनी सतह का गंभीर क्षरण, भूमि का धंसान, कोयला खदानों में आग लगना और अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुईं।

भूमिगत आग से प्रभावितों को समुचित रूप से बसाने की तैयारी की जा रही है। फाइल

हालांकि आग प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए साल 2009 में झरिया मास्टर प्लान बना था। 2009 के झरिया मास्टर प्लान में आग, भू-स्खलन से निबटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए मंजूरी दी थी। 2021 तक अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए दूसरी जगहों पर आवास बनाकर उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाना था, लेकिन अब तक ये दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं। 2019 में कराए गए सर्वे में पता चला कि अग्नि और भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की संख्या बढ़कर एक लाख चार हजार हो गई है। अब 16 साल बाद संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है।

आजीविका सृजन पर भी जोर : संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) योजना में पुनर्वासित परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सृजन पर अधिक जोर है। लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। पुनर्वासित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आय-सृजन के अवसर पैदा किए जाएंगे। ऐसे परिवारों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जाएंगी साथ ही आजीविका अनुदान और संस्थागत ऋण भी दिए जाएंगे। इसके अलावा, पुनर्वास स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई, सीवरेज, स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र, सामुदायिक हाल और अन्य सामान्य सुविधाएं भी होंगी।

जमीन के नीचे भी आग से नुकसान : धरती के गर्भ में लगभग 100 वर्षों से धधक रही आग ने धरती के नीचे कितना नुकसान पहुंचाया होगा, इसका आकलन अबतक नहीं हुआ है, लेकिन इसकी भी चिंता की जानी चाहिए पर्यावरण से लेकर वायुमंडल में जानलेवा गैस की उपस्थिति से कई खतरे उत्पन्न हुए हैं। इसका सटीक आकलन भविष्य के अध्ययनों पर निर्भर करेगा। सतह पर यह विभीषिका अलग-अलग रूपों में नजर आती रहती है। कोयले में लगी आग जमीन के भीतर ही भीतर आगे बढ़ रही है और अपने पीछे राख छोड़ती जा रही है।

कोयले की राख जमीन में होने वाले विचलन के क्रम में दबती व खिसकती है, जिससे ऊपर की जमीन धंस जाती है। अब तक दर्जनों लोगों के घर इस तरह के भूधंसान से बने गोफ में समा चुके हैं। कई लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है।

मंथन

ट्रांसजेंडर के लिए नई राह

प्रियम वर्मा
priyam.verma@nda.jagran.com

केरल उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय को एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस निर्णय ने कई ट्रांसजेंडर के लिए नया कानूनी मार्ग प्रशस्त किया है

सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता केरल हाई कोर्ट का वह आदेश आजकल चर्चा में है, जिसमें उसने एक ट्रांसजेंडर जोड़े को राहत प्रदान की। इस फैसले ने एक नई चर्चा को जन्म दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता और पिता शब्दों का उपयोग न करते हुए, दोनों को केवल माता-पिता लिखा जाए और उनके लिंग का उल्लेख न किया जाए। अदालत ने कोझीकोड नगर निगम को संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। यह भारत में अपने तरह का पहला मामला है। इस जोड़े को अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता की जगह स्वयं को लिंग निरपेक्ष माता-पिता लिखने की स्वीकृति प्राप्त हो गई।

यह मामला केरल के ट्रांसजेंडर जोड़े जिया (पिता) और जाहद (माता) का है। जिया एक पुरुष के रूप में पैदा हुई और बाद में ट्रांसफार्मेशन के बाद वह महिला में बदल गई। जाहद एक महिला के रूप में पैदा हुआ और ट्रांसफार्मेशन से एक पुरुष बन गया। जाहद ने महिला से पुरुष में बदलने की प्रक्रिया में गर्भ धारण किया था। लिंग परिवर्तन के बाद अब जिया ट्रांसवुमन है और जाहद ट्रांसमैन। दोनों ने अनुरोध किया था कि चूंकि बच्ची की जैविक माता जाहद इस समय समाज में पुरुष के रूप में हैं, इसलिए अब उन्हें इसी पहचान से दर्शाया जाए।

इससे पहले कोझीकोड नगर पालिका ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया था कि उन्हें माता और पिता की जगह लिंग निरपेक्ष माता-पिता (अभिभावक) लिखा जाए। इसके खिलाफ याचिका में केरल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 सभी प्रकार के लैंगिक पूर्वाग्रह और लिंग आधारित भेदभाव पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 19 (1) (ए) ट्रांसजेंडर्स को अपनी पसंद की लिंग पहचान चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 में यह माना गया है कि लैंगिक पहचान, सम्मान के मौलिक अधिकार के केंद्र में है। केरल हाई कोर्ट के फैसले से जिया और जाहद को अब वह पहचान मिलेगी, जिस रूप में वे समाज में रह रहे हैं।

वस्तुतः 25 वर्षीय जिया और 24 वर्षीय जाहद दो साल पहले तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपनी उन तस्वीरों को जारी किया, जिसमें जाहद प्रेग्नेंट नजर आ रहे थे। इसके बाद जाहद ने कोझीकोड के सरकारी मेडिकल कालेज में एक लड़की को जन्म दिया। केरल उच्च न्यायालय का फैसला एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। एलजीबीटीक्यू में 'एल' का मतलब लेस्बियन है, 'जी' का गे, 'बी' का बाइसेक्सुअल और 'टी' का आशय ऐसे ट्रांसजेंडर से है, जिसका व्यवहार जन्म के समय के लिंग के विपरीत होता है। बाद में इसमें 'क्यू' जोड़ा गया, जिसका मतलब होता है क्वीयर यानी जो अपने यौन रुझान को लेकर असमंजस में होते हैं।

केरल उच्च न्यायालय का फैसला कई ट्रांसजेंडर के लिए एक नया कानूनी मार्ग प्रशस्त करता है। यह संयोग ही है कि हर साल जून में ही 'प्राइड मंथ' मनाया जाता है। जून में मनाए जाने वाले प्राइड मंथ की शुरुआत 1969 के अमेरिका के स्टोनवाल (न्यूयार्क) में हिंसा के बाद हुई थी। यह हिंसा इसलिए हुई थी, क्योंकि पुलिस समलैंगिकों के यहां छापा डालने गई थी। प्राइड मंथ मनाने का मकसद समलैंगिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। अक्टूबर में मनाया जाने वाला 'हिस्ट्री मंथ' ट्रांसजेंडर समुदाय के अतीत पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 1994 में अमेरिका में हिस्ट्री मंथ की शुरुआत हुई और 2000 के बाद इसमें टी और क्यू भी जोड़ा गया। इस तरह इस समुदाय को एलजीबीटीक्यू कहा जाने लगा।

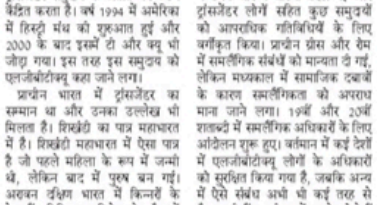

प्राचीन भारत में ट्रांसजेंडर का सम्मान था और उनका उल्लेख भी मिलता है। शिखंडी का पात्र महाभारत में है। शिखंडी महाभारत में ऐसा पात्र है जो पहले महिला के रूप में जन्मी थी, लेकिन बाद में पुरुष बन गई। अरावन दक्षिण भारत में किन्नरों के देव हैं। ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में उनके बारे में धारणा बदल गई और ट्रांसजेंडर सहित कुछ समुदायों को आपराधिक गतिविधियों के लिए वर्गीकृत किया। फिर ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में उनके बारे में धारणा बदल गई और ट्रांसजेंडर लोगों सहित कुछ समुदायों को आपराधिक गतिविधियों के लिए वर्गीकृत किया। प्राचीन ग्रीस और रोम में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई, लेकिन मध्यकाल में सामाजिक दबावों के कारण समलैंगिकता को अपराध माना जाने लगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समलैंगिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हुए। वर्तमान में कई देशों में एलजीबीटीक्यू लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है, जबकि अन्य में ऐसे संबंध अभी भी कई तरह से गैरकानूनी हैं। अफ्रीका में 31 देश ऐसे हैं जो इन लोगों को किसी न किसी रूप में अपराधी मानते हैं।

प्रतीकात्मक

****

कल्पमेधा

मैने बातूनी व्यक्ति से मौन सीखा है। इसी तरह, असहिष्णु व्यक्ति से सहिष्णुता और दयाहीन व्यक्ति से दयालुता सीखी।

- खलील जिब्रान

दोहरे पैमाने

आतंकवाद के मसले पर समूची दुनिया में एक राय देखी जाती है कि जब तक इसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा नहीं खोला जाएगा, इस पर पूरी तरह काबू पाना संभव नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात की अपेक्षा और मांग की जाती है कि किसी भी देश या समूह को इस मामले में दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मगर आतंकवाद की समस्या से उपजी फिक्र तब बेमानी हो जाती है जब क्षेत्रीय सहयोग के लिए गठित देशों के किसी समूह में आतंक का सामना करने को लेकर दोहरे पैमाने अपनाए जाते हैं। गौरतलब है कि चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में जो साझा बयान तैयार किया गया, उसमें बलूचिस्तान का उल्लेख तो किया गया, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले और उसकी प्रकृति को सभी देश आतंकवाद का एक क्रूर चेहरा ही मानते हैं और उसके खिलाफ अभियान चलाने को लेकर प्रतिबद्धता जताते रहते हैं। लेकिन विचित्र है कि एससीओ की बैठक में आतंकवाद से लड़ाई के संदर्भ में पहलगाम हमले को दर्ज करना जरूरी नहीं समझा गया।

इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि इस बैठक में तैयार संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और साफतौर पर कहा कि यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को नहीं दिखाता। इसके बाद यह सम्मेलन बिना संयुक्त बयान जारी किए ही समाप्त हो गया। यह जगजाहिर हकीकत रही है कि भारत में आतंकवाद की समस्या को जटिल बनाने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस तथ्य को दुनिया के ज्यादातर देश भली-भांति जानते हैं। खुद चीन के बेजिंग में कुछ वर्ष पहले हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के घोषणापत्र में इस तथ्य को शामिल किया गया था कि कई बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। फिर पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमलों में भी पाकिस्तान से आए आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद एससीओ सम्मेलन के संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया जाना क्या दर्शाता है?

सवाल है कि इस सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संगठन के सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं, तो भारत में आतंकवाद पर उनके दोहरे पैमाने दुनिया के सामने इसके खिलाफ लड़ाई का कैसा रास्ता तैयार करेंगे। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान आतंकवाद को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शह देने की अघोषित नीति पर काम करता है और अपनी सीमा में आतंकवादियों को पनाह देता रहा है! भारत में घुसपैठ से लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी हमलों का सिरा कहां से जुड़ा होता है, यह छिपा नहीं है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद चीन आमतौर पर पाकिस्तान के हक में खड़ा दिखता रहा है। एससीओ की बैठक के संयुक्त बयान में भी पहलगाम को शामिल न कर बलूचिस्तान का जिक्र करने की कोशिश क्या चीन का पाकिस्तान को स्पष्ट समर्थन नहीं है? आतंकवाद पर ऐसे दोहरे पैमाने के साथ इसके खिलाफ किस तरह की लड़ाई का दावा किया जा सकता है? इस संदर्भ में भारत ने उचित ही एससीओ के देशों, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।

नशे का दायरा

पंजाब पिछले दो दशक से नशाखोरी की चपेट में है। मादक पदार्थों की लत युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। गांवों तक पहुंच चुके तस्कर उनके लिए मौत के सौदागर बन गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के प्रयास और संकल्प के बावजूद समस्या गहराती चली गई है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया। मगर सच यह है कि नशाखोरी पर लगाम लगाने में किसी दल की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती। जब भी नशे के खिलाफ अभियान चलता है, तो पर्दे के पीछे से कई लोग बाधक बन जाते हैं। ऐसे आरोप आम रहे हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के तार राजनीति से जुड़े हैं। अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। उन पर मादक पदार्थों से अर्जित 540 करोड़ से अधिक राशि का कई माध्यमों से शोधन करने का आरोप है। सवाल है कि पंजाब के युवाओं को खोखला करने में लगे वे कौन लोग हैं, जिन पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है। अब पंजाब की मौजूदा राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव पर मजीठिया की गिरफ्तारी का जो भी असर पड़े, लेकिन इससे एक व्यापक तंत्र का संकेत जरूर मिलता है।

हालांकि मादक पदार्थों के कारोबार को संरक्षण देने के मामले को लेकर राजनीतिकों पर जब-तब सवाल उठते रहे हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य का हवाला देकर राजनीति करने वाले लोग ही अगर नशाखोरी को बढ़ावा देंगे, तो कैसी युवा पीढ़ी तैयार होगी? सतर्कता जांच के बाद मादक पदार्थों के कारोबार में विक्रम सिंह मजीठिया के लिप्त रहने के आरोप ने इस आशंका को बल दिया है कि क्या इस मामले में कुछ और चेहरे छिपे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि पिछले एक दशक से लगातार अभियान चलाने के बावजूद अपनी जड़ें जमाए नशे के सौदागर काबू नहीं आ रहे? हैरत की बात है कि राज्य में जब भी नशे का मुद्दा उठा, मजीठिया का नाम भी चर्चा में रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भगवंत मान ने उनको निशाने पर लिया था। अब उन पर कार्रवाई के बाद अकाली नेता इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि राजनीतिक बयानबाजी में असल मुद्दा पीछे न छूट जाए।

साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियां

आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और जीवन के सभी पहलुओं को कमोबेश प्रभावित कर रहा है। किसी को आनलाइन परेशान करना, बौद्धिक संपदा की चोरी, जासूसी और वायरस समेत कई ऐसे प्रारूप हैं, जो अपराध के लिहाज से परेशानी का सबब हैं।

सुशील कुमार सिंह

इस वर्ष देश की करीब नब्बे करोड़ आबादी इंटरनेट से जुड़ जाएगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता का स्तर कहां तक विकसित हो पाया है। हालांकि, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक-2024 के पांचवें संस्करण में भारत ने 'टियर-1' का दर्जा प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि तो हासिल की है, मगर चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। वर्षों पहले साइबर अपराध की बढ़ती स्थिति और इलेक्ट्रानिक प्रणाली से गतिमान संदर्भ को देखते हुए यह अनुमान लगा लिया गया था कि देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े रोजगार में बढ़ोतरी होगी। सरकार को साइबर सुरक्षा के मसले पर सख्त नियम और कानून तैयार करने होंगे। आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और जीवन के सभी पहलुओं को कमोबेश प्रभावित कर रहा है। साइबर जागरूकता और सावधानी इसका प्राथमिक बचाव है, मगर जिस देश में (2011 की जनगणना के अनुसार) हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित या अल्पशिक्षित हो, वहां साइबर शिक्षा कितनी सबल होगी, यह समझना कठिन नहीं है। किसी को आनलाइन परेशान करना, बौद्धिक संपदा की चोरी, वायरस, भयादोहन और फिरौती समेत कई ऐसे प्रारूप हैं, जो अपराध के लिहाज से परेशानी का सबब हैं।

इस वर्ष बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में साइबर हमले को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2020 से 2024 तक साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की संख्या में लगभग 76.25 फीसद की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में साइबर हमलों की संख्या वर्ष 2022 में 13.91 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 15.92 लाख हो गई और 2024 में यह आंकड़ा 20.41 लाख तक पहुंचा। इस वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वर्ष 2013 से पहले भारत में कोई स्पष्ट साइबर नीति नहीं थी, मगर अब ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 सुरक्षा और जागरूकता में सुधार लाने की इच्छा से युक्त है। इसी वर्ष भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केंद्र की स्थापना की गई, जबकि 2017 में साइबर स्वच्छता केंद्र और 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल जैसी कवायद शुरू हुई थी।

गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी कई संधियों पर दस्तखत किए हैं। डिजिटल दुनिया में आपसी सीमाएं कम होती जा रही हैं। ऐसे में एक मजबूत वैश्विक शासन प्रणाली साइबर खतरों से निपटने के लिए कारगर हो सकती है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे सुनिश्चित हो पाएगा कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए एक समान दृष्टिकोण हो और सभी हितधारक एक साथ मिलकर काम करें, ताकि एक सुरक्षित आनलाइन वातावरण बनाया जा सके। वर्ष 2024 में भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में चार गुना वृद्धि हुई, जो हर रोज करोड़ों डिजिटल वित्तीय लेनदेन वाले देश में बढ़ते जोखिमों को रेखांकित करता है। मार्च 2025 में वित्त मंत्रालय द्वारा

संसद में प्रस्तुत आंकड़ों से यह भी पता चला है कि मार्च 2024 को समाप्त वित्तवर्ष में लोगों ने धोखाधड़ी में कुल 2.03 करोड़ डालर खो दिए, जो वित्तवर्ष 2023 की राशि से दोगुने से भी अधिक है। ऐसे मामलों की कुल संख्या जहां राशि एक लाख रुपए या उससे अधिक

> यह तय है कि देश में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी। डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी साइबर अपराध के बड़े आधार बन गए हैं। शायद यही कारण है कि रोजगार के नए अवसर में आनलाइन निजी जानकारी की सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ी है। देखा जाए तो साइबर सुरक्षा का बाजार भी बड़ा आकार लेता जा रहा है। एक रपट से यह पता चलता है कि इस बाजार का आकार वर्ष 2021 में 220 करोड़ का था, जिसके 2027 तक 350 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

थी, पिछले वर्ष 6,699 से बढ़कर 29,082 हो गई।

ऐसा नहीं है कि साइबर हमले और उसके नुकसान में भारत अकेला देश है। सच्चाई यह है कि इसकी मार से सभी देश त्रस्त हैं और नित नए मरहम की खोज में लगे हैं। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) की नवीनतम साइबर अपराध रपट के अनुसार, वर्ष 2024 में साइबर अपराध के कारण अमेरिका में अनुमानित 16.6 अरब डालर का नुकसान हुआ, जो वर्ष 2023 में दर्ज 12.5 अरब डालर से 33 फीसद अधिक है। वहीं, साइबर अपराध के कारण यूरोप को प्रतिवर्ष खरबों डालर का नुकसान होता है। पिछले साल जर्मन कंपनियों ने तो साइबर अपराध के कारण 266.6 अरब यूरो खो दिए और ब्रिटेन में व्यवसायियों को वर्ष 2021 में साइबर अपराध के कारण अनुमानित 73.6 करोड़ पाउंड का नुकसान हुआ। वैसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक जनवरी 2025 की रपट पर नजर डालें तो इसमें भू-राजनीतिक तनाव, अप्रचलित प्रणालियों और साइबर सुरक्षा कौशल के अभाव के चलते महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बढ़ते साइबर खतरे को समझा जा सकता है। साइबर हमले से शायद ही कोई देश बच पाया हो। ऐसे में वैश्विक शासन का दृष्टिकोण कुछ हद तक आवश्यक प्रतीत होता है। वैश्विक शासन का आशय अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर नियमों, मानदंडों, और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली से है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को न केवल पार करती है, बल्कि यह आर्थिक विकास, व्यापार, मानवाधिकार, शांति व सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों का समाधान निकालने का मार्ग प्रशस्त करता हो। जाहिर है, ऐसे में साइबर सुरक्षा को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो वैश्विक चुनौतियों का रूप ले चुका है।

यह तय है कि देश में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी। डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी साइबर अपराध के बड़े आधार बन गए हैं। शायद यही कारण है कि रोजगार के नए अवसर में आनलाइन निजी जानकारी की सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ी है। देखा जाए तो साइबर सुरक्षा का बाजार भी बड़ा आकार लेता जा रहा है। एक रपट से यह पता चलता है कि इस बाजार का आकार वर्ष 2021 में 220 करोड़ का था, जिसके 2027 तक 350 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देखा जाए तो 2021 में साइबर हमलों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था और 2022 में इसे लेकर 14 लाख मामले दर्ज किए गए थे। अब तो ये आंकड़े और बड़ा रूप ले चुके हैं। विज्ञान और तकनीक ने जो मुकाम हासिल किया है, उसमें सब कुछ उजला ही नहीं है, कुछ उसके स्याह पक्ष भी हैं, साइबर अपराध इसी का एक नतीजा है।

मौजूदा दौर में ई-गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर महत्त्व दिया जा रहा है। इंटरनेट संपर्क या 'कनेक्टिविटी' 5-जी से 6-जी की ओर कदम बढ़ा चुकी है। पढ़ाई-लिखाई से लेकर चिकित्सा और अदालती व्यवस्थाओं में इंटरनेट का पूरा समावेश देखा जा सकता है। ई-बैंकिंग समेत दर्जनों प्रकार की इलेक्ट्रानिक विधाओं से युक्त क्रियाकलापों को जमीन पर उतारा गया है। लेन-देन की प्रक्रिया का व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। मगर साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह सोचना होगा कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस के साइबर सेल और सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जन मानस को खुद को भी जागरूकता और सावधानी का स्तर बढ़ा लेना चाहिए।

शिक्षा की रोशनी

राजेंद्र जोशी

व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक एक दशक बाद भारत में जनगणना होती है। जनगणना के आंकड़ों से साक्षरता दर का आकलन होता है। आजादी के बाद 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद साक्षरता के क्षेत्र में तेज गति से काम होने लगा। 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। इस दौरान अनेक प्रदेशों की साक्षरता दर में उछाल आया। इस दशक में साक्षरता के क्षेत्र में उत्तर भारत में उत्साह और उमंग के साथ सराहनीय काम हुआ, जहां साक्षरता प्रतिशत पचास फीसद से भी कम था।

उस दौरान केरल 93.91 फीसद साक्षरता दर के साथ देश में नंबर एक पर था तो मिजोरम 91.58 फीसद साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर था। अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएफएलएस रपट के मुताबिक, मिजोरम 98.20 फीसद साक्षरता दर हासिल कर देश का पहला पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता अभियान और सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित होने लगे और धीरे-धीरे साक्षरता अभियानों ने कार्यक्रम का स्थान ले लिया। यहीं से साक्षरता कार्यक्रम बन गया और साक्षर होने की गति और उत्साह भी कम होने लगा। मिजोरम में फिर से साक्षर होने की कार्ययोजना तैयार कर उल्लास कार्यक्रम के तहत फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई।

निरक्षर व्यक्ति को केवल साक्षर बनाना ही मकसद नहीं होता, नवसाक्षरों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होता है। यह बात मिजोरम ने समझी। प्रदेश के आर्थिक स्तर को सुधारने, भविष्य उन्नयन और नवसाक्षरों को व्यावसायिक कौशल देने के प्रयास भी किए। संपूर्ण साक्षरता अभियान की तरह सरकार ने जनता के सहयोग से निरक्षरता उन्मूलन के लिए स्वयंसेवक तैयार किए, उन्हें प्रशिक्षण दिया, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई, स्वयंसेवकों के साथ सरकार के प्रतिनिधि और अफसर नियमित संपर्क में बने रहे। प्रदेश भर में साक्षरता के पक्ष में वातावरण बनाया गया, वातावरण निर्माण के तहत घर-घर सर्वेक्षण किया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, असाक्षरों का सम्मान किया गया। उनके साथ निरंतर संपर्क रखा गया। इस कार्यक्रम में असाक्षर की पहचान, मूल्यांकन और निरीक्षण का काम प्रतिदिन होता रहा। क्लस्टर बनाकर क्षेत्र आधारित कार्यक्रम तैयार किए गए। छोटे-छोटे समूह बनाए गए, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और समाज के व्यक्ति, जो साथ मिलकर असाक्षर व्यक्ति के घर जाते, उनसे आग्रह करते।

समुदाय के सहयोग से संचालित साक्षरता अभियान के अंतर्गत स्थानीय भाषा और गहरी सांस्कृतिक सहायता से लोगों ने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो ज्ञान को महत्त्व देने लगे। शिक्षित नागरिक से ही एक समग्र और विकसित राष्ट्र और समाज की परिकल्पना की जा सकती है।

यह अच्छी और सुखद खबर है। मिजोरम की साक्षरता यात्रा देश के अन्य प्रदेशों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। 2011 में 91.58 फीसद लोग साक्षर थे। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि केवल आठ फीसद लोगों को ही साक्षर करने का काम था। दिखने में और सुनने में आठ फीसद का लक्ष्य तय करना कोई बड़ी बात न हो, पर यही वह समूह था, जिसको साक्षर करना मुश्किल काम था। शिक्षा से दूर रहे इस समूह की मानसिकता बदलना मुश्किल ही नहीं कठिन काम होता है, जिसे मिजोरम ने अपनी इच्छा शक्ति से कर दिखाया।

नब्बे के दशक में केरल संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। केरल से पहले एर्नाकुलम जिले को संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। वहां भी संपूर्ण साक्षरता अभियान को जन आंदोलन बनाया गया था। केरल सरकार ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिलकर यह काम किया। वहां भी उस समय केवल नौ फीसद लोगों को ही साक्षर करना था, लेकिन वे भी 'हार्डकोर ग्रुप' यानी शिक्षा से दूर रहे समूह की श्रेणी में थे। केरल की साक्षरता यात्रा घर, गांव और जिला स्तर तक चली। केरल में प्रत्येक सरकारी अधिकारी जन सहयोग से अपनी जिम्मेदारी समझकर निरक्षरता उन्मूलन के पवित्र काम में लगा था। केरल की तर्ज पर पूरे देश में साक्षरता अभियान संचालित हुआ। उसी तकनीक को मिजोरम सरकार ने भी जन सहयोग से अपनाया और संपूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया।

दरअसल, घने बांस के जंगलों और पहाड़ियों, गहरी घाटियों के कारण 'हार्डकोर समूह' की पहचान करना भी चुनौतीपूर्ण था। मिजोरम सरकार के लिए अब चुनौती इस बात की है कि ये लोग अभ्यास छूटने के बाद फिर से असाक्षर की श्रेणी में न आ जाएं। प्राथमिक शिक्षा में शत-प्रतिशत नामांकन हो और स्कूली पढ़ाई बीच में न छूटे। नवसाक्षरों की साक्षरता सतत बनी रहे, इसलिए व्यावसायिक कौशल के साथ जोड़ना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। उनको रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत होगी, जिससे उनकी साक्षरता कायम रहेगी।

ऐसी इच्छाशक्ति यह बताती है कि जब समुदाय और सरकार मिलकर काम करते हैं तो असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से पूर्ण राज्य बनने के बाद इतने कम समय में पूर्ण साक्षर होना राज्य के लिए गर्व की बात है। अब निरंतरता में शिक्षा की मुहिम चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मौजूदा उपलब्धि की रोशनी मिजो समाज को रोशन करे।

दुनिया मेरे आगे

> निरक्षर व्यक्ति को केवल साक्षर बनाना ही मकसद नहीं होता, नवसाक्षरों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होता है। यह बात मिजोरम ने समझी। प्रदेश के आर्थिक स्तर को सुधारने, भविष्य उन्नयन और नवसाक्षरों को व्यावसायिक कौशल देने के प्रयास भी किए।

साख का सवाल

'सख्ती और सवाल' (संपादकीय, 23 जून) पढ़ा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने कंपनी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सभी दायित्व मुक्त करने का आदेश दिया है। यह जरूरी था। इस भयावह विमान हादसे ने टाटा समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। इस समूह के हाथ में जाने के, बाद एअर इंडिया में सुधार की जो उम्मीद की गई थी, वह पूरी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि सौदे के समय जो कर्मचारी-अधिकारी एअर इंडिया में कार्यरत थे, समझौते के तहत उनका भी समायोजन कंपनी को करना था। फिलहाल विमान हादसे के बाद से एअर इंडिया की बुकिंग में 20 फीसद की कमी आई है। विमान यात्रियों का विश्वास डगमगा रहा है। हालिया जांच में पाया गया है कि एअर इंडिया के दो विमानों ने लंदन के लिए उड़ान भरते समय निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है। इसके अलावा उड़ान के दौरान भी छिटपुट घटनाएं सामने आईं। नतीजतन, विमानों को गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में आपात स्थिति में उन्हें उतारना पड़ा। यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। विमान सेवा को सुरक्षित बनाना ही होगा।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम

उद्योग और रोजगार

'आर्थिक चुनौतियों से जूझते छोटे उद्यम' (लेख, 24 जून) पढ़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इन उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। निर्यात में इनका योगदान है, रोजगार की दृष्टि से भी ये अच्छे माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही भारत लघु और कुटीर उद्योगों में उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है। करोड़ों हाथों को काम देने वाले देश के छोटे उद्यम लंबे समय से कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हर दिन उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। आज आयातित तकनीक के युग में इनकी मांग पर असर पड़ा है। गांवों को बचाना है, तो हमें छोटे उद्योगों पर ध्यान देना होगा, ताकि शहरों की तरफ पलायन रुक सके। जब तक इन उद्योगों का पहिया तेजी से नहीं चलाया जाएगा, तब तक रोजगार पैदा नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें छोटे उद्योगों पर ध्यान देना होगा। इसकी अभी जरूरत है।

- साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

वर्चस्व की होड़

इजराइल और ईरान के बीच दशकों पुराना वैचारिक, सामरिक और रणनीतिक विरोध रहा है। इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच संघर्ष विराम ने पूरी दुनिया को राहत की सांस लेने का अवसर दिया है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इजराइल इस बात पर अड़ा है कि जब तक वह ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइल के जखीरे को समाप्त नहीं कर देता है, तब तक हमले जारी रहेंगे। सैन्य कारवाई के बाद यह विराम क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक तेल आपूर्ति और आर्थिक संतुलन के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। संघर्ष विराम के उपरांत ईरान द्वारा जीत का एलान करना पाकिस्तान के दावों की याद दिलाता है। इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अनगिनत निर्दोष लोगों की जान गई। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी, गहन वैचारिक मतभेद और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ इस विराम को कभी भी तोड़ सकती है।

- हिमांशु शेखर, गयाजी

श्रम की कीमत

'जानलेवा सफाई' (24 जून) पढ़ा। प्रत्येक वर्ष कई कर्मचारी सीवर की सफाई करते समय मौत के मुंह में समा जाते हैं। दरअसल, सीवर की सफाई के दौरान उससे निकलने वाली जहरीली गैस जानलेवा साबित होती है। यह सफाई कर्मियों की मौत की वजह बनती है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। यह भी कहा गया कि सफाई कर्मी जब भी सीवर में उतरें, तो वे आधुनिक उपकरणों से लैस हों। उस समय वहां संबंधित अधिकारी उपस्थित हों, क्योंकि यह बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। इसलिए वहां किसी अधिकारी का मौजूद होना जरूरी है। दुखद ही है कि आज भी कर्मियों को आधुनिक उपकरण नहीं दिए जाते। प्रायः बिना किसी उपकरण के उनको सीवर में उतार दिया जाता है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

- मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 27 जून 2025

चौंकाने वाली जीत

अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यू यॉर्क में जोहरान ममदानी की सफलता केवल चुनावी जीत नहीं, बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर Andrew Cuomo को पराजित किया। ममदानी अब इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं।

जनता से संवाद । भारतीय जड़ों वाले 33 साल के इस युवा नेता ने उन लोगों की आवाज उठाई, जो न्यू यॉर्क की चकाचौंध में हाशिये पर समझे जाते हैं। उन्होंने टीवी स्टूडियो, ऑनलाइन इंटरव्यू और महंगे विज्ञापनों से ज्यादा तवज्जो जनता से सीधे संवाद को दी। वह सड़कों पर उतरे, गलियों में गए और आम लोगों से बातचीत कर उनकी नब्ज जानी। न्यू यॉर्क का वर्किंग क्लास इस शहर में बढ़ते खर्च से परेशान है, ममदानी ने इसके समाधान का वादा किया है।

ममदानी मेयर पद के करीब

मध्यम वर्ग की ताकत । उनके वादों पर गौर करें, तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किराये पर लगाम, न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दे एक नजर में न्यू यॉर्क जैसे शहर के अजेंडे से बाहर की चीज लगते हैं, लेकिन ममदानी की जीत से जाहिर होता है कि मध्यम वर्ग की समस्या हर जगह एक जैसी है। इस वर्ग को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जो उनकी परेशानियों को समझ कर उनका हल पेश कर सके। जोहरान ममदानी ने बिल्कुल यही किया।

युद्ध का फैक्टर । जोहरान ममदानी को प्रोग्रेसिव माना जाता है। वह उदार हैं, युवा हैं और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखते हैं - खासकर इस्राइल-हमास जंग के मसले पर उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया। इसे भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। अमेरिकी जनता जंग से त्रस्त आ चुकी है। यूक्रेन हो या गाजा - लड़ाई के खर्च का एक बड़ा हिस्सा उसकी जेब से जा रहा है। फिर गाजा में पैदा हुई मानवीय त्रासदी ने भी इस्राइली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा पैदा किया है। ऐसे में ममदानी का साफ स्टैंड लेना लोगों को भा गया।

आगे बड़ी चुनौती । ममदानी ऐसे वक्त उभरे हैं, जब ट्रंप प्रशासन प्रवासियों को लेकर बेहद सख्त है। वह इस बात के प्रतीक हैं कि अमेरिका में अब भी सपनों के लिए जगह है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां कई हैं। उनकी उम्मीदवारी तय होने के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उन पर निशाना साधा। वह खुद भी ट्रंप की नीतियों के आलोचक रहे हैं। उनके कुछ बयानों-प्रदर्शनों से भारतीय कम्युनिटी भी नाराज है। अभी तक की उनकी सियासत किसी आंदोलनकारी जैसी रही है, लेकिन अब उनसे ज्यादा परिपक्वता की अपेक्षा होगी।

रोज़-ब-रोज़

सेल्फी की राजधानी

शैलेंद्र पांडेय

अमेरिकी फटॉग्रफर और रसायनशास्त्री Robert Cornelius ने कैमरा सेट किया, बटन दबाया और फिर टहलते हुए सामने जाकर खड़े हो गए। सन 1839 में उन्होंने अपनी जो तस्वीर ली थी, उसे बहुत लोग दुनिया की पहली सेल्फी मानते हैं। हालांकि तब न सेल्फी शब्द दुनिया में आया था और न रॉबर्ट का ऐसा कुछ करने का इरादा था। वह तो कैमरे ही इतने स्लो थे तब कि खुद से खुद की तस्वीर आराम से खींची जा सकती थी। इसी वजह से रॉबर्ट या उनके दौर के लोगों को सेल्फी की लत न लगी, वरना तो इटली के फ्लोरेंस में स्थित Uffizi Gallery की मुसीबत और बढ़ जाती! सेल्फी के चक्कर ने इस गैलरी में सजी 300 साल पुरानी एक मशहूर पेंटिंग का कबाड़ा कर दिया। इटली के कलाकार Anton Domenico Gabbiani ने 1712 में Tuscany के राजकुमार का यह पोर्ट्रेट बनाया था। पिछले दिनों एक शख्स इसके सामने खड़े होकर बिल्कुल वही पोज देने की कोशिश कर रहा था, जो तीन सदियों पहले राजकुमार ने दिया था। लेकिन, बैलेंस बना नहीं, वह शख्स पीछे गिरा और राजकुमार के शरीर पर मुक्के बराबर छेद हो गया। Uffizi गैलरी और दुनिया भर के म्यूजियम अब सोच रहे हैं कि कैसे विजिटर्स को कला का सम्मान सिखाया जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में म्यूजियम में जाने से पहले आपको एक गाइडलाइन पढ़नी पड़े - 'कैसे लें तस्वीर, बिना कुछ तोड़े!'

सेल्फी शब्द का चलन 2002 के आस-पास ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट स्लैंग के रूप में शुरू हुआ। साल 2013 में यह ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का Word of the Year भी बना। इससे जुड़ा सबसे दिलचस्प कानूनी विवाद वह था, जहां यह तय करने के लिए करीब 8 साल लंबी मुकदमेबाजी चली कि बंदर की खींची सेल्फी पर हक बंदर का है या कैमरे वाले का। लेकिन, अब परेशानी यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार Selfie की आदत Selfitis बन चुकी है - एक तरह की लत। अनुमान के मुताबिक, दुनियाभर में हर दिन 9 करोड़ सेल्फी ली जाती हैं और भारत इसमें सबसे आगे है। तो गाइडलाइन की जरूरत अब हर जगह है - नदियों के किनारे, समुद्र तटों, पुलों और सर्पिले पहाड़ी रास्तों पर।

एकदा

क़लम की ताक़त

इटली के नुआरो स्थित सार्डिनिया द्वीप में 1871 में एक बच्ची ने जन्म लिया। वह अपने सात भाई-बहनों के बीच चौथे क्रम पर थी। उन दिनों लड़कियों को नाममात्र की शिक्षा दी जाती थी। यह बच्ची भी केवल चार साल तक पढ़ पाई। उसके पिता के पास लोगों का जमघट लगा रहता। वे अपनी दुखभरी कहानियां उस बच्ची के पिता को सुनाया करते थे। बच्ची भी उन कहानियों को सुनती। पिता को लिखने का शौक था, तो यह गुण बच्ची में बचपन से ही आ गया। वह भी छिप-छिपकर कागजों पर कुछ न कुछ लिखती रहती। स्कूल से निकलने के बाद भी वह पुस्तकों से दूर नहीं हो पाई। 13 साल की उम्र में जब उसकी पहली रचना प्रकाशित हुई तो वह खुशी से झूम उठी। कुछ ही समय में उसका विवाह हो गया। वह अपने पति Palmiro Madesani के साथ रोम चली गई। पति भी लिखने में उसका पूरा साथ देता। उसका पहला उपन्यास 'Fior de Sardegna (The Flower of Sardinia)' 1892 में प्रकाशित हुआ, जिसने धूम मचा दी। वह वास्तविकता को अपनी रचना के धरातल पर बुनती रही। जल्द ही वह इटली की श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में जानी जाने लगी। उसकी रचनाओं में लोगों के मौन की आवाज रहती। 1926 में उसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज पूरी दुनिया इस लेखिका को Grazia Deledda के नाम से जानती है।

Subrata Dhar

संकलन : रेनू सैनी

चार दशक पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उससे कहीं अलग है यह सफ़र

भारत को क्या मिलेगा शुभांशु की यात्रा से

चंद्रभूषण

देश के लिए यह गौरव से ज्यादा उत्सुकता और कल्पना का समय है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना अब से 41 साल पहले सोवियत संघ के सहयोग से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा द्वारा इसी कारनामे की याद दिलाता है, लेकिन चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष से धरती के दर्शन करके लौट आना था, लेकिन शुभांशु शुक्ला को इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन पर एक हफ्ते से ज्यादा का समय बिताना है, कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं, और सबसे बढ़कर, ऐसे तजुर्बे जमा करने हैं जो आगे गगनयान मिशन में काम आएंगे।

अंतरिक्ष का इंसानी ठीहा । धरती से चार सौ किलोमीटर ऊपर निरंतर घूमता हुआ यह स्पेस स्टेशन सन 2000 से अंतरिक्षयात्रियों के ठहरने और वैज्ञानिक प्रयोग करने की जगह बना हुआ है। शीतयुद्ध समाप्त होने की अकेली श्रेष्ठ साझा सौगात के रूप में हमारे पास यह इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन (ISS) ही है। कुल 500 टन वजनी इस चीज को अलग-अलग भेजे गए 43 टुकड़े जोड़कर बनाया गया है। 150 अरब डॉलर लागत के साथ यह इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इसके उपयोग में कुछ हिस्सा भारत का भी होना चाहिए था, लेकिन यह मौका हमें पहली बार मिल रहा है।

PTI

भाड़े पर अंतरिक्षयात्रा । ध्यान रहे, राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा में एक बुनियादी फर्क यह भी है कि शर्मा जी को यह अवसर भारत और रूस की पुरानी दोस्ती के नतीजे में मिला था, जबकि शुक्ला जी को आकाश में भेजने के लिए भारत सरकार को 6 करोड़ 40 लाख डॉलर, यानी तकरीबन 550 करोड़ रुपये नकद गिनने पड़े हैं। किसी देश से दोस्ती या दुश्मनी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लोगों से तगड़ा भाड़ा वसूलकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनकी तैयारी कराना, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट बुक करके उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाना, कुछ दिन उन्हें स्पेस स्टेशन में किराये के एक कमरे में रखना, फिर वापस लाना अमेरिकी कंपनी 'ऐक्जियम स्पेस' का धंधा है, और फिलहाल यह उसका चौथा मिशन है।

मिशन पायलट का ओहदा । हर मिशन में कुल चार सीटें उपलब्ध होती हैं, जिनमें तीन 'पेड' होती हैं जबकि एक, मिशन कमांडर कंपनी की ओर से जिम्मेदार होता है। इस बार के मिशन ऐक्जियम-4 या ऐक्स-4 में कमांडर की भूमिका निभा रही पेगी व्हिट्सन पुरानी अंतरिक्षयात्री और कंपनी की कर्मचारी हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जेब से या अपनी सरकारों की जेब से ऐक्जियम स्पेस को करोड़ों डॉलर दे रखे होते हैं, उनका रुतबा बढ़ाने के लिए कंपनी की ओर से उन्हें भी कुछ ओहदे दिए जाते हैं। जैसे इस बार शुभांशु शुक्ला को मिशन पायलट और बाकी दोनों अंतरिक्षयात्रियों को मिशन स्पेशलिस्ट कहा गया है।

साल में दो मिशन । ट्रेनिंग में सबको क्रू (कर्मी) माना जाता है, सबका एक-एक बैक-अप होता है, और उड़ान से लेकर डॉकिंग तक हर काम हर एक को सिखाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा से राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने की संभावना दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, क्योंकि रूस-अमेरिका के ऑफिशल मिशंस के अलावा ऐक्जियम स्पेस के दो मिशन हर साल स्पेस स्टेशन जाते हैं। ऐसे में सारे देशों के नाम धीरे-धीरे इसमें जुड़ते जाएंगे।

स्पेस शटल का संकट । इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन की बदलती नियति का किस्सा भी हमें थोड़े में जान ही लेना चाहिए। 2008 की ग्लोबल मंदी जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कस-बल ढीले करने लगी तो बजट कटौती के बीच नासा ने 2009 में अपनी सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजा कि 2016 तक वह इस सफेद हाथी का खेल खत्म कर देगा। उसकी बेचैनी के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि ISS को सप्लाई पहुंचाने, वहां से गंदगी वापस लाने और बाकी मेंटिनेंस का काम स्पेस शटल किया करती थी, लेकिन 2003 में कल्पना चावला वाले हादसे के बाद अमेरिका ने सारी शटल सेवाओं को क्रमशः समाप्त कर देने का फैसला कर लिया था।

क्या है मिशन मे खास

- राकेश शर्मा अंतरिक्ष से धरती दर्शन कर लौट आए थे
- शुभांशु शुक्ला स्पेस में कई तरह के अहम प्रयोग करेंगे
- गगनयान मिशन में काम आएगा शुभांशु का तजुर्बा

आपदा में अवसर । 2018 में अमेरिकी संसद ने ISS को आगे भी चलाते रहने का फैसला किया, लेकिन 2022 में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और अमेरिका ने रूस से सारे वैज्ञानिक संबंध तोड़ लिए तो एक समय स्पेस स्टेशन के नाम से लोगों को दहशत होने लगी थी। गनीमत यही रही कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनियों ने इसको आपदा में अवसर की तरह लिया और थोड़ी वैज्ञानिक आभा देकर स्पेस स्टेशन को एक किस्म के होटल की तरह इस्तेमाल करने लगीं।

अपने स्पेस स्टेशन की योजना । अभी 2030 में इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देने और उसकी जगह पांच प्राइवेट अमेरिकी स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर अमल हो रहा है। चीनियों ने अपना अलग स्पेस स्टेशन बना रखा है, हालांकि उसका आकार ISS का एक तिहाई है। भारत में भी 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेने की एक योजना पाइपलाइन में है, तो इसकी दिमागी तैयारी के लिए अभी हमें शुभांशु शुक्ला की हर हरकत में हिस्सा लेना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

हमारे इनोवेशन के केंद्र में हैं आम नागरिक

जितेन्द्र सिंह

अतीत पर गौर करते हुए आज कोई भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि प्रौद्योगिकी से प्रेरित परिवर्तन के 11 साल भारत के भावी उत्थान के सूचक हैं। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के उस विजन का प्रमाण हैं - जहां प्रयोगशालाएं लॉन्च पैड बन चुकी हैं और नवाचार (इनोवेशन) राष्ट्रीय विकास का नया मुहावरा बन चुका है।

अनुसंधान पर ध्यान । परिवर्तन की शुरुआत अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने से हुई। 2023 में अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRAF) की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार भारत ने रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ अपने अनुसंधान और विकास (R&D) इकोसिस्टम के संचालन के लिए एक वैधानिक निकाय बनाया।

क्वांटम कंप्यूटिंग पर फोकस । हम सिर्फ अनुदान देने तक ही सीमित नहीं रहे, हमने भी संस्थान बनाए। IIT और IISC में चार विषयगत केंद्रों के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन देश को क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहा है।

भविष्य की तैयारी । वैज्ञानिक प्रगति का सही मापदंड इससे प्रभावित होने वाले जीवन में है। IIT बॉम्बे में विकसित स्मार्ट एग्री-स्टेशन दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को रियल टाइम में मिट्टी और मौसम की स्थिति की निगरानी में सक्षम बनाता है। IIT भिलाई का दिव्यांग ATM दृष्टिबाधित नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तक सम्मान भरी पहुंच देता है। 46 महिला प्रौद्योगिकी पार्क बने, जिन्होंने 11,000 से अधिक महिलाओं को वैज्ञानिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया है। हमने 29 राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र बनाए हैं और 2,000 से अधिक शोधपत्रों और 1,000 रिपोर्टों में सहायता दी है। हिमालय के ग्लेशियरों की मैपिंग से लेकर 1.8 लाख से अधिक हितधारकों को प्रशिक्षित करने तक हम भारत को अनुकूलन, प्रतिक्रिया और नेतृत्व के लिए भी तैयार कर रहे हैं।

जमीन पर अधिकार । मानव पूंजी में हमारा निवेश भी उतना ही परिवर्तनकारी रहा है। इंस्पायर कार्यक्रम ने विश्वविद्यालयों के 75,000 से अधिक छात्रों और 6,800 डॉक्टरेट शोधकर्ताओं को सहायता दी है। मानक योजना 2.5 लाख से अधिक स्कूल-स्तरीय नवाचारों को राष्ट्रीय मंच पर लाई है। वहीं, पूर्वोत्तर अब केसर की खेती और ड्रोन-आधारित भू-स्थानिक मानचित्रण का केंद्र बन गया है। नेक्टर और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से 2 लाख से अधिक गांवों का 10 सेमी रिजॉल्यूशन के साथ मानचित्रण किया गया है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार और सुरक्षा की नई भावना मिली है।

कॉमन रूम

निजी क्षेत्र से सहयोग । हमारे युवाओं में प्रतिभा और हमारी नीतियों में दृढ़ता है। 2025-26 के बजट में घोषित 1 लाख करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष मात्र एक वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि इरादे की घोषणा है। 20,000 करोड़ रुपये के समर्पित आवंटन और डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ, हम निजी क्षेत्र को भारत के वैज्ञानिक भाग्य के सह-लेखन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

दुनिया संग कदमताल । आगे की राह चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी दोनों है। AI, रोबॉटिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान जैसी उभरती तकनीकों के लिए न केवल निवेश, बल्कि कल्पना की भी दरकार होगी। हमारा काम केवल दुनिया के साथ तालमेल रखना ही नहीं है, बल्कि रुख निर्धारित करना है। ऐसा करते हुए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे- चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में कोई जनजातीय किसान हो, झारखंड की कोई स्कूली छात्रा हो, या बेंगलुरु का स्टार्टअप संस्थापक।

(लेखक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं)

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

दूब-घास की तरह कोमल बन जाइए सबसे मान मिलेगा

सीताराम गुप्ता

हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के विषय में कहा जाता है कि यह विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। संयुक्त वर्णों या व्यंजनों - जैसे श्र, प्र, क्र, ग्र, द्र, म्र आदि का होना भी इसकी एक विशेषता है। इनमें पहला वर्ण वैसा ही रहता है यानी बड़ा, लेकिन उसमें जो 'र' वर्ण जुड़ता है, वह बहुत छोटा होता है। ऐसे वर्ण, जो किसी वर्ण के नीचे या पैर की तरफ लगाए जाते हैं, पदेन वर्ण कहलाते हैं। स्थान पैरों में, लेकिन रुतबा पैर वाले से अधिक। यह व्यवस्था हम सब पर भी लागू होती है।

जब हम किसी के पैरों के पास बैठ जाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे के रहस्य को समझना जरूरी है। हालांकि पैरों के पास बैठना या झुकना सबके लिए सरल और सहज नहीं होता। लेकिन यह साधना या तपस्या की तरह है। किसी के चरणों में बैठना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक विनम्रता का प्रतीक है। यह कठिन इसलिए भी लगता है क्योंकि इसके लिए केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी झुकना पड़ता है। मन और आत्मा से झुकने के लिए आध्यात्मिक समझ जरूरी है।

जब तक हममें किसी भी दृष्टि से बड़े होने का दंभ बना रहता है, हम किसी के पैरों के पास नहीं बैठ सकते और बड़े होने का अवसर गंवा देते हैं। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं या साथ रहते हैं, या मिलकर काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उनके सामने छोटे बनकर रहते हैं या उन्हें अधिक महत्त्व देते हैं। लेकिन, ऐसा कर हम खुद बड़े हो जाते हैं।

नानक देव ने कहा है - नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े-बड़े बह जात हैं दूब खूब की खूब। उनका कहना है कि यदि दूब जैसे नन्हे बने रहोगे तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूब एक प्रकार की घास है, जिसकी कई विशेषताएं हैं। दूब छोटी होती है, कोमल होती है। जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो वह चुपचाप दब जाती है और पैर हटते ही फिर खड़ी हो उठती है। आंधी-तूफान, बाढ़ या तेज बारिश में बड़े-बड़े पेड़ उखड़कर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूब का कुछ नहीं बिगड़ता।

दूब इतनी नन्ही होती है कि कोई उससे ईर्ष्या नहीं करता। दूब की तरह ही जो छोटे होकर रहते हैं, उनसे भी कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता। उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। लघुता के कई लाभ हैं। हमारी वाणी में भी लघुता यानी विनम्रता होना चाहिए। हम विनम्र बने रहते हैं तो हम न केवल नष्ट नहीं होते, बल्कि सीखते भी हैं। विनम्र हुए बिना कोई कुछ नहीं सीख सकता - न जीवन मूल्य और न जीवन जीने की कला। जो सिखाने वाले को जितना अधिक मान देता है, जितना उसके सामने विनम्र होकर बैठता है, उतना ही अधिक सीखता है। लघुता में ही छिपा है संपूर्णता का सूत्र।

दूरसंचार ग्राहकों की सुरक्षा पर ही है हमारा सबसे अधिक ध्यान

स्पैम कॉल्स, फोन हैकिंग और साइबर अटैक जैसी समस्याओं से निपटने के सरकार के प्रयासों से इन मामलों में बड़ी कमी आई है। दूरसंचार मंत्री **ज्योतिरादित्य सिंधिया** का कहना है कि टेलिकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत के लिए दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ चुका है। उनसे बात की NBT के **अखिलेश प्रताप सिंह** ने। पेश हैं प्रमुख अंश :

■ मोबाइल फोन हैकिंग से लेकर स्पैम कॉल्स तक कई समस्याएं हैं। इन पर क्या किया जा रहा है?

सरकार के लिए उपभोक्ता के हित सर्वोपरि हैं। भारत ही नहीं, दुनियाभर में स्पैम कॉल्स, मोबाइल चोरी, हैकिंग की तमाम शिकायतें आती हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने इस दिशा में चार कदम उठाए हैं। संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप की व्यवस्था की गई। इनके आधार पर करीब ढाई करोड़ मोबाइल डिसकनेक्ट किए, जिनसे अवैध ट्रांजैक्शन हुए थे। करीब 3 लाख वट्सऐप अकाउंट कैंसल किए गए। राष्ट्रभर के नक्शे के आधार पर डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट भी बनाई गई है, जिसमें बैंकों, फाइनैंशल इंस्टिट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाओं, होम मिनिस्ट्री सहित सभी संस्थाओं की भागीदारी है। देसी सॉल्यूशन से फायरवॉल बनाई गई है ताकि देश के अंदर कोई साइबर अटैक करना चाहता है तो निपटा जा सके। लोगों को विदेशी नंबरों से जो स्पैम कॉल्स आती थीं, उनको बंद करने के इंतजाम किए गए हैं। हर दिन 1.30 करोड़ कॉल्स ब्लॉक किए। इतने टारगेटेड तरीके से बंद किए हैं कि अब ऐसी कॉल्स केवल 6 लाख प्रतिदिन तक सीमित हो गई हैं। भारत के 120 करोड़ दूरसंचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

विशुद्ध राजनीति
इंटरव्यू

■ प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले BSNL के सुस्त पड़ जाने के आरोप लगते हैं...

BSNL बनाम प्राइवेट का मुद्दा है ही नहीं। हर टेलिकॉम ऑपरेटर के पास अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने का अवसर है। BSNL के उपभोक्ता पिछले साल जून में 8.55 करोड़ थे, अब 9 करोड़ हैं। 2007 के बाद पहली बार यह कंपनी प्रॉफिट में आई है। दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ और मार्च तिमाही में 280 करोड़ रुपये का प्रॉफिट रहा। पिछले वित्त वर्ष में रेवेन्यू साल भर पहले से 11% बढ़ा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोगुना हो गया है।

■ आरोप यह भी है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर असेंबलिंग हो रही है, क्या कहेंगे?

हमेशा कहा जाता था कि भारत में सर्विसेज की क्षमता है। BSNL के लिए 4G की बात आई तो पीएम मोदी ने तय किया कि विदेशी उपकरण नहीं खरीदे जाएंगे। तब सरकारी कंपनी C-Dot और प्राइवेट सेक्टर की तेजस और TCS के साथ मिलकर 24 महीनों में सॉल्यूशन निकाला गया। इसका कार्यान्वयन आज BSNL के 1 लाख टावरों में हो रहा है। इनमें से पिछले सालभर में ही करीब 94 हजार टावर लग चुके हैं और 70 हजार एक्टिव हो चुके हैं। 2014 में करीब 70% मोबाइल फोन हम लोग आयात करते थे। आज भारत विश्व की दूसरी बड़ी प्रॉडक्शन फैसिलिटी बन चुका है। करीब 2 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल फोन का निर्यात हो रहा है। इसमें हम लोगों का 99% अपना प्रॉडक्शन है। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि टेक्नॉलजी के किसी एक हिस्से से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग ही भारत में हो रही है।

■ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर 11 वर्षों में किन कार्यों को आप खास मानते हैं?

2014 में हमारे पास करीब 90 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता थे, आज 120 करोड़ से ज्यादा हैं। इंटरनेट उपभोक्ता करीब 25 करोड़ थे, आज 97 करोड़ हैं। ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 6 करोड़ थे, आज 94 करोड़ हैं। देश में प्रति जीबी डेटा की कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है।

■ इस डिजिटल क्रांति से क्या फर्क पड़ा है?

आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। विश्व के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। यहां वर्ष में 1.72 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। कुल मिलाकर साल में 2.82 ट्रिलियन डॉलर के लेनदेन आज भारत में होते हैं। भारत से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर और UPI की टेक्नॉलजी लेने के लिए विकसित देश आतुर हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ समझदारी से काम लें

26 जून के लेख 'ईरान पर भारत से क्या भूल हुई है' अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को बहुत संतुलित रूप में सामने लाता है। एक आम भारतीय के तौर पर लगता है कि भारत को न तो इस्राइल का अंध समर्थन करना चाहिए और न ही ईरान से दूरी बनानी चाहिए। दोनों देशों के साथ हमारे रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। ईरान INSTC और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि इस्राइल से तकनीकी और रक्षा सहयोग चलता है। ऐसे में कोरी भावुकता नुकसानदेह साबित हो सकती है। बदलते वैश्विक समीकरणों को देखते हुए हमें विवेकशीलता और समझदारी से अपना रुख तय करना चाहिए।

गोविंद परमार, ईमेल से

■ समाज का सच

26 जून को 'आधी दुनिया' कॉलम में प्रकाशित लेख 'कर सकती है कायापलट' पढ़ा। रिद्धिमा सावंत ने कॉरपोरेट जगत में महिलाओं की स्थिति पर जो अपने अनुभव और विचार शेयर किए हैं, वह सराहनीय है। उन्होंने अपनी कंपनी में ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर दिया है जो महिलाओं के विकास की बात करता है। यह भी है कि वर्कफोर्स का हिस्सा बनने को तैयार ऊर्जावान लड़कियों का पहला टकराव अपने परिवार से ही होता है। फिर आसपास का समाज और पुरुष साथी रही-सही कसर पूरी कर देते हैं। आधुनिक सोच की बात सिर्फ कहने की है। फिर भी यह 21वीं सदी की नारी है, टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। लेकिन इसके लिए हर लड़की को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी।

मोनिका जैन, इंदिरापुरम

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

सऊदी प्रिंस से पाक ने कहा, भारत से बात के लिए तैयार है - एक खबर - और उधर परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल बना रहा है।

सत्येन्द्र प्रसाद